● वर्ष-2
● अंक-207
रायपुर, शुक्रवार
21 अप्रैल 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmailÐcom

कोरोनाः हर रोज 50 हजार मरीज बढ़ेंगे

पिछले पांच दिन में 49 हजार 970 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए , 24 घंटे में 29 लोगों की संक्रमण से मौत

नई दिल्ली। देश में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले पांच दिन में 49 हजार 970 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 65 हजार 286 हो गई है। ये ऐसे मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटे के अंदर 29 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। इस बीच, संक्रमण के प्रसार और आने वाले दिनों में स्थिति को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों ने तीन बड़े दावे किए हैं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल ने गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर दावा किया है कि मई मध्य में कोरोना पीक पर होगा। रोजाना 50 हजार तक केस आएंगे। इसके बाद संक्रमण में उतार भी देखने को मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, यह कोविड की लहर नहीं है।

पिछले पांच दिनों के मरीज

16 अप्रैल	10,093
17 अप्रैल	9111
18 अप्रैल	7,633
19 अप्रैल	10,542
20 अप्रैल	12,591

डरने की जरूरत नहीं है।

प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल ने गणितीय मॉडल सूत्र से पहले भी संक्रमण के उतार-चढ़ाव व पीक का सही आकलन दिया है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कोरोना को लेकर रणनीति भी बनाई है। इस बार उनका कहना है कि बदला म्यूटेंट समझकर डरने की जरूरत नहीं है। अभी 10 हजार से ज्यादा केस रोज आ रहे हैं। यह आंकड़ा 50 हजार तक पहुंचेगा लेकिन स्थिति गंभीर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नेचुरल इम्युनिटी कम होने की वजह से ऐसा हुआ है। जून में स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। लोगों में वायरस से लड़ने की क्षमता कम हुई है, यही वजह है कि संक्रमण बढ़ रहा है।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिक डॉ. रजनीकांत ने आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल के दावे को खारिज कर दिया। डॉ. रजनीकांत ने कहा कि गणितीय मॉडल के आंकड़े विश्वास लायक नहीं हैं। सभी को रियल टाइम डेटा पर फोकस करना चाहिए। जो दावे किए जा रहे हैं, वो बेकार हैं।

आने वाले दिनों में मामले कम हो जाएंगे

डॉ. रजनीकांत ने आगे कहा, कोविड को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। सबकुछ काबू में है। आने वाले दिनों में कोरोना के मामले फिर कम हो जाएंगे। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखना चाहिए। जिन्हें भी हल्का लक्षण महसूस हो, वह मास्क पहनें। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जानें से बचें। अगर कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जरूर लगवा लें। कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के अलावा प्रिकॉशन डोज भी लगवाएं। डॉ. रजनीकांत से जब हमने सवाल पूछा कि अगर मामले बढ़ते हैं तो उन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या हम तैयार हैं? उन्होंने कहा कि हां, अब देश में कोविड से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। कोविड जांच के लिए पर्याप्त संख्या में लैब्स हैं। आरटी-पीसीआर के अलावा एंटीजन और सेल्फ टेस्ट किट पर्याप्त हैं। अस्पतालों में भी सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ऐसे में किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

वायरस पूरी तरह से कभी नहीं खत्म होगा

वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. समीरन पांडा ने कहा कि अब कोरोना के साथ ही लोगों को रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये वायरस पूरी तरह से कभी नहीं खत्म होगा। हां, एक टाइम के बाद इंफ्लूएंजा की तरह जरूर हो सकता है। डॉ. समीरन ने आगे कहा, कोरोना एक समय एंडेमिक स्टेज में पहुंच जाएगा। ये भी फ्लू और बुखार जैसा हो जाएगा। जैसे- इंफ्लूएंजा का प्रकोप हर साल कम या ज्यादा हो जाता है ठीक उसी तरह कोरोनावायरस के केस हर साल कम या ज्यादा आएंगे। एक समय था इंफ्लूएंजा एक बहुत बड़ी महामारी थी, लेकिन आज वह अपनी एंडेमिक स्टेज में है यानी वह आज भी आबादी के बीच कभी कम और कभी ज्यादा के रूप में है।

भारत में मृत्यु दर 5-8 गुना कम

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में दावा किया गया है कि आयरन, जिंक और फाइबर से भरपूर भारतीय आहार, चाय के नियमित सेवन और भोजन में हल्दी के इस्तेमाल से देश में कोविड के कारण गंभीरता और मृत्यु में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान, कम आबादी वाले पश्चिमी देशों की तुलना में घनी आबादी वाले भारत में मृत्यु दर कथित तौर पर 5-8 गुना कम थी। भारत, ब्राजील, जॉर्डन, स्विटजरलैंड और सऊदी अरब सहित वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा किए गए इस अध्ययन का उद्देश्य यह जांचना था कि क्या आहार संबंधी आदतें कोविड-19 की गंभीरता और पश्चिमी और भारतीय आबादी के बीच मौतों में भिन्नता से जुड़ी थीं। भारतीय आहार के घटक ने कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) और लिपोपॉलीसेकेराइड (एलपीएस)-मध्यस्थता वाले कोविड-19 गंभीरता को रोकने में भूमिका निभाई। इसके अलावा, भारतीयों द्वारा चाय के नियमित सेवन से उच्च एचडीएल (उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन) को बनाए रखने में मदद मिली, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। चाय में कैटेचिन रक्त में ट्राइग्लिसराइड को कम करने में एक प्राकृतिक एटोरवास्टेटिन (हृदय रोगों को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्टैटिन दवा) के रूप में भी काम करता है। भारतीयों द्वारा रोज भोजन में हल्दी के नियमित सेवन से एक मजबूत प्रतिरक्षा बनी रही। शोधकर्ताओं ने कहा कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन ने सार्स कोव-2 संक्रमण और कोविड-19 की गंभीरता से जुड़े रास्ते और तंत्र को रोका और मृत्यु दर को कम किया। दूसरी ओर, रेड मीट, डेयरी उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत के परिणामस्वरूप पश्चिमी आबादी में कोविड के कारण गंभीरता और मृत्यु में वृद्धि हुई।

इन दिनों

✍ अमित शर्मा

भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग

भाजपा ने कर्नाटक के लिए जारी अपनी 189 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में ही ये संकेत दे दिए थे कि इस बार वह सत्ता में वापसी के लिए सोशल इंजीनियरिंग का दांव आजमाएगी। पार्टी के सभी 224 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने के बाद यह और साफ हो गया है कि दिग्गज नेताओं की नाराजगी के बाद भी वह विभिन्न जातियों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी और बड़ी जीत की राह तलाश करेगी। पार्टी ने 64 लिंगायत उम्मीदवारों को टिकट देकर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की है, तो 45 वोक्कालिगा उम्मीदवारों को टिकट देकर कुमारस्वामी के वोट बैंक में भी सेंधमारी करने की कोशिश की है। उसने ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय को भी पर्याप्त भागीदारी देकर उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर एक संपूर्ण समाज समावेशी पार्टी होने का संदेश दिया है। उसे इसका लाभ मिल सकता है। लिंगायत समुदाय भाजपा के साथ पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है और बीएस येदियुरप्पा जैसे दिग्गज लिंगायत नेताओं के साथ होने से पार्टी को अनुमान है कि यह वर्ग इस बार भी उसके साथ बना रहेगा। इसी वर्ग से आने वाले जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी जैसे नेता अब कांग्रेस के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा ने इन दिग्गज नेताओं को टिकट देने से इनकार कर दिया था। इन बागियों के कारण पार्टी को नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन भाजपा नेताओं का दावा है कि लिंगायत समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने के कारण बागी नेता बेअवसर हो जाएंगे और समुदाय का साथ उन्हें मिलता रहेगा। कर्नाटक में वोक्कालिगा दूसरा सबसे प्रभावी समुदाय माना जाता है। लगभग 15 फीसदी मतदाता वाला यह समुदाय अभी तक जेडीएस के साथ माना जाता है। लेकिन राज्य में अपने दम पर सत्ता में आने के लिए भाजपा इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की जीतोड़ कोशिश कर रही है। इसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने इस वर्ग के 45 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यदि इस किसान-मजदूर वर्ग का एक हिस्सा उसके साथ आ जाता है तो भाजपा की सत्ता की राह आसान हो सकती है। भाजपा एक रणनीति के अंतर्गत ओबीसी-दलित समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी यह कोशिश केंद्र सरकारों के साथ-साथ राज्य सरकारों और पार्टी संगठन के स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। इसी रणनीति पर चलते हुए पार्टी ने कर्नाटक में 37 दलित उम्मीदवारों को टिकट थमाया है, तो ओबीसी समुदाय के 32 लोगों को टिकट दिया है। अनुसूचित जनजाति के लोगों को 18 टिकट देकर भाजपा ने उन्हें भी साधने की कोशिश की है। भाजपा ने कर्नाटक में केवल 10 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया है। दक्षिण भारत की दलित-ओबीसी केंद्रित राजनीति में दूसरे दलों की ओर से उसके ब्राह्मण नेतृत्व को लेकर हमेशा प्रश्न खड़े किए जाते रहे हैं। लेकिन इस सूची में भाजपा ने पूरी तरह ब्राह्मणों को अपनी प्राथमिकता सूची से बाहर कर दिया है। दूसरे समुदायों में इसका बेहतर संदेश गया तो लंबी अवधि में यह भाजपा के पक्ष में जा सकता है। उसका यह रुख उसे तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी ताकत प्रदान कर सकता है।

मुखर्जी नगर में अभ्यर्थियों से मिले राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे थे। मुखर्जी नगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के लिए जाना जाता है। यहां हजारों की तादाद में एसएससी और यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं रहते हैं। इन्हीं से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। इस दौरान राहुल गांधी ने छात्रों से पूछा कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है? राहुल के साथ प्रियंका गांधी का बेटा रेहान वाड्रा भी मौजूद रहा। इस दौरान राहुल गांधी और छात्र-छात्राएं काफी सहजता से अपनी बात रखते दिखाई दे रहे हैं।

यूनीसेफ ने टीकाकरण के लिए की भारत की तारीफ

नई दिल्ली। यूनिसेफ ने कोरोना टीकाकरण को लेकर भारत की तारीफ की है। यूनिसेफ के अनुसार, भारत 55 में से उन तीन देशों में से एक है जहां कोविड-19 महामारी के बाद भी टीकों के महत्व की धारणा बनी रही या उनमें सुधार हुआ। हालांकि, भारत दुनिया के उन देशों में भी शामिल है जहां कई बच्चों को कोरोना वैक्सीन की एक भी खुराक (शून्य-खुराक) नहीं दी गई। भारत में ऐसे बच्चों की संख्या 27 लाख है, जिन्हें एक भी नियमित टीका नहीं दिया गया है।

यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ विवेक वीरेंद्र सिंह ने कहा, कोरोना महामारी के दौरान शून्य-खुराक वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 30 लाख हो जाने के बावजूद, भारत 2020 और 2021 के बीच शून्य-खुराक वाले बच्चों की संख्या को कम करके 27 लाख तक लाने

में सक्षम हुआ। इसके लिए चौथा गहन मिशन इन्द्रधनुष और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के इसके निरंतर प्रावधान सहित सरकार द्वारा शुरू की गई अटूट राजनीतिक प्रतिबद्धता और निरंतर साक्ष्य-आधारित अभियानों को धन्यवाद देता हूं। यूनिसेफ ने अपनी वार्षिक फ्लैगशिप रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन- 2023 में कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान 55 देशों में से 52 देशों में बच्चों के लिए टीकों के महत्व की सार्वजनिक धारणा में गिरावट आई है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे के लिए टीकाकरण से पता चलता है कि महामारी की शुरुआत के बाद दक्षिण कोरिया, पापुआ न्यू गिनी, घाना, सेनेगल और जापान में बच्चों के लिए टीकों के महत्व की धारणा में एक तिहाई से अधिक की गिरावट आई है।

द वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट द्वारा एकत्र और यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित नए आंकड़ों में चीन, भारत और मैक्सिको ही ऐसे देश हैं जिनका अध्ययन किया गया है। अध्ययन के आंकड़ों ले संकेत मिला है कि इन देशों में टीकों के महत्व की धारणा बनी रही या इसमें सुधार हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है, अधिकांश देशों में 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों और महिलाओं में महामारी की शुरुआत के बाद बच्चों के टीकों के बारे में कम विश्वास की रिपोर्ट दर्ज की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अध्ययन किए गए 55 देशों में से लगभग आधे देशों में 80 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने टीकों को बच्चों के लिए महत्वपूर्ण माना, इसके बावजूद टीके को लेकर कम विश्वास देखा गया है। हालाकि, रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कई कारकों के मिलने से पता चलता है कि वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट का खतरा बढ़ रहा है। इन कारकों में महामारी की प्रतिक्रिया के बारे में अनिश्चितता, भ्रामक जानकारी तक बढ़ती पहुंच, विशेषज्ञता के विश्वास में कमी और राजनीतिक ध्रुवीकरण शामिल हैं।

प्रमुख समाचार

20 से अधिक रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री

बेंग्लुरू। कर्नाटक चुनाव में भाजपा अपनी पूरी ताकत लगा रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही भरोसा करे रही है। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी 20 से अधिक रैलियां करेंगे। भाजपा के प्रचार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे अन्य स्टार प्रचारक भी शामिल होंगे। कर्नाटक एकमात्र दक्षिणी राज्य है जहां पार्टी सत्ता में है और 2024 के आम चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण चुनावी दंगल है। भाजपा पीएम मोदी के लिए एक कार्यक्रम तैयार कर रही है। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल के बाद कर्नाटक में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। इसको लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी जानकारी दी है।

नरोदा गाम मामले में सभी आरोपी बरी

अहमदाबाद। गुजरात के नरोदा गाम दंगे मामले में अहमदाबाद की विशेष जस्टिस एसके बक्शी की अदालत 68 आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। दरअसल, 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद शहर के नरोदा गाम इलाके में सांप्रदायिक हिंसा में 11 लोग मारे गए थे। इस मामले में 86 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज है। हालांकि, 86 में से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात की पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी भी 86 आरोपियों में शामिल थे। इससे पहले बीते दिन विशेष अभियोजक सुरेश शाह ने कहा था कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष ने 2010 में शुरू हुए मुकदमे के दौरान क्रमशः 187 और 57 गवाहों का परीक्षण किया और लगभग 13 साल तक चले इस मामले में छह न्यायाधीश सुनवाई कर चुके हैं। सितंबर 2017 में भाजपा के वरिष्ठ नेता (अब केंद्रीय गृह मंत्री) अमित शाह भाजपा नेता माया कोडनानी के बचाव पक्ष के गवाह के रूप में अदालत के समक्ष पेश हुए थे।

सबको छोड़ा, फिर मैं क्यों जेल में हूं- सिसोदिया

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय से उन्हें जमानत देने का आग्रह किया और दावा किया कि कथित

अपराध की आय से उन्हें जोड़ने वाला कोई मनी ट्रेल अभी तक नहीं मिला है। मनीष सिसोदिया को पहले एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। आप के वरिष्ठ नेता के वकील ने कहा कि सिसोदिया मामले में गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं हैं। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि सीबीआई जैसा चाहती है वैसा जवाब देने के लिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आगे कोर्ट से कहा कि हाल ही के निर्णय हैं जहां अदालतों ने यह विचार किया है कि सह-आरोपी को जमानत भी जमानत का एक आधार है। आप मुझसे फोन मांगते हैं, मैंने उन्हें स्पष्टीकरण दिया है कि मेरे पास फोन नहीं है। जहां तक जांच का संबंध है, आप यह नहीं कहते कि फोन में क्या था।

15 दिन में तीन विधायकों का प्रशासनिक पदों से इस्तीफा

इंफाल। भाजपा विधायक पाओनाम ब्रोजेन ने गुरुवार को निजी कारणों से मणिपुर डेवलपमेंट

सोसाइटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ब्रोजेन पूर्वोत्तरी राज्य से तीसरे पार्टी विधायक हैं जिन्होंने एक पखवाड़े के भीतर मणिपुर सरकार के अपने संबंधित प्रशासनिक पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों विधायक कथित तौर पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मिलने और अपनी शिकायतों को दर्ज कराने के लिए दिल्ली में थे। उनके इस कदम से अटकलें लगाई जा रही थीं कि एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में मतभेद पैदा हो रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं निजी कारणों से मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी, इंफाल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। ब्रोजेन ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को लिखे पत्र में कहा, इसे स्वीकार किया जाए।

खत्म हुआ असम-अरुणाचल सीमा विवाद, एमओयू पर हुआ हस्ताक्षर

गुवाहाटी। असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में एक अंतर-राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा और अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के समाधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि आज, हमने एक विकसित, शांतिपूर्ण और संघर्ष-मुक्त पूर्वोत्तर की स्थापना के लिए मील का पत्थर पार कर लिया है। अमित शाह ने कहा कि 1972 से आजतक इस सीमा विवाद को सुलझाया नहीं जा सका। उन्होंने कहा कि लोकल कमिशन की रिपोर्ट 1972 से अबतक अलग-अलग सरकारों में अदालतों में विवाद से ग्रस्त रही। उस रिपोर्ट को दोनों राज्य की सरकारों ने स्वीकार कर लगभग 800 किलोमीटर की असम- अरुणाचल सीमा विवाद आज समाप्त कर लिया है।

सिविल सेवा दिवस

राज्य में कुछ नौकरशाहों के पास राजनेताओं से ज्यादा ताकतः धनखड़

देव कश्यप

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा कि राज्य स्तर पर कुछ नौकरशाहों के पास राजनेताओं की तुलना में अधिक शक्ति है। उन्होंने आत्मनिरीक्षण और उनकी काउंसलिंग करने का आह्वान किया ताकि सिविल सेवा को लेकर जो लोगों का विश्वास है उसके अनुरूप वे काम कर सके। सिविल सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में राजनीतिक आकाओं की मिलीभगत, संघीय ढांचे पर दबाव और पारदर्शिता एवं जवाबदेही को नुकसान पहुंचाने के कारण भारत के मजबूत ढांचे को कमजोर किया जा रहा है।

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने 16वें सिविल सेवा दिवस के दो दिवसीय समारोह के उद्घाटन के मौके पर कहा कि राज्य स्तर पर कुछ नौकरशाह राजनेताओं के लिए एक वास्तविक चुनौती बन रहे हैं। उनके पास अधिक शक्ति है जिससे कोई भी राजनेता ईर्ष्या कर सकता है। इस मामले में आत्मनिरीक्षण और उनकी काउंसलिंग करने की आवश्यकता है ताकि उनकी सेवा लोगों के उस विश्वास के अनुरूप बनी रहे, जिसका प्रतिष्ठा के साथ दशकों से पालन किया गया है।

उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण मुद्दे आपस में उलझने के बजाय समाधान की मांग करते हैं। उन्होंने कहा, अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 और संबंधित कानूनी व्यवस्था का ईमानदारी से पालन करना वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। उन्होंने नियमों के एक प्रावधान का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है एक सिविल सेवक के लिए यह अनिवार्य है कि जब वह

अपने वरिष्ठ अधिकारी से मौखिक निर्देश प्राप्त करता है, उसके बाद जल्द से जल्द लिखित में इसकी पुष्टि करेगा। धनखड़ ने कहा कि कुछ मामलों में इसका उल्लंघन देखा गया है।

उपराष्ट्रपति ने कहा, यह एक संवैधानिक अनिवार्यता है कि केंद्र और राज्यों के प्रशासन में एकरूपता होनी चाहिए ताकि संघवाद सहकारी संघवाद में विकसित हो सके जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्पना की थी। उन्होंने कहा, मुद्दों का हल करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि सिविल सेवा की प्रभावकारिता और उदात्तता खो न जाए। धनखड़ ने कहा कि नौकरशाही स्वाभाविक रूप से विधायिका, न्यायपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका के हस्तक्षेप से ग्रस्त है। उन्होंने कहा, इन संस्थानों से सद्भाव में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। वे टकराव में नहीं आ सकते। वे शिकायतकर्ता मोड में नहीं हो सकते। उन्हें सहयोगी रूप में रहना होगा ... इसके लिए हम सभी को काम करना चाहिए। यदि हमारे लोकतंत्र को फलते-फूलते और बनाए रखना है तो शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का पालन करना होगा

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संगठनों से खतरे निकल रहे हैं, जिसमें कुछ विदेशी विश्वविद्यालय देश की सभ्यता लोकाचार को ध्वस्त करने और इसके विकास को प्रभावित करने के लिए विध्वंसक भारत विरोधी गतिविधियों के केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में तथाकथित अभिजात वर्ग के छिपे हुए एजेंडे में परेशान करने वाली अंतर्दृष्टि खतरनाक है और दुर्भाग्य से यह हमारे संवैधानिक संस्थान के कामकाज में दिखाई दे रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह आंतरिक या बाहरी किसी भी प्रकार के खतरों से भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता और सांस्कृतिक अखंडता की रक्षा करे। 16वें सिविल सेवा दिवस के उद्घाटन समारोह में धनखड़ ने कहा कि अभूतपूर्व विकास और वैभव की राह पर चल रहे हमारे लोकतंत्र को जरूरत है कि उसके पंख - विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका सुचारू रूप से ऊपर की उड़ान के लिए मिलकर काम करें। हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा, हमारी सभ्यता के लोकाचार को ध्वस्त करने और हमारे विकास को प्रभावित करने के लिए विध्वंसक भारत विरोधी गतिविधियों के केंद्र के रूप में काम करने वाले कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों सहित, भीतर और बाहरी संगठनों से खतरे निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद अकेले कानून की प्रभारी है और इसे लागू करने में सक्षम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए धनखड़ ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत के अभूतपूर्व विकास और फलते-फूलते लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति शुतुरमुर्ग का रुख अपनाते हैं। ऐसे लोगों को सहन करना वाकई दर्दनाक होता है।

मौत के डर से नाम वापस लिया, एसपी ने दी थी एनकाउंटर की धमकी : मंतूराम पवार

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 2014 के अंतागढ़ उपचुनाव से चर्चा में आए पूर्व विधायक मंतूराम पवार ने इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने अंतागढ़ उपचुनाव के विवाद का जिन्न एक बार फिर बाहर कर दिया है। मंतूराम पवार ने उपचुनाव में नाम वापस लेने के पीछे मौत का डर बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांकेर के तत्कालीन एसपी ने उन्हें एनकाउंटर की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि, इस सबंध में न्यायालय में भी अपना बयान दर्ज करा चुके हैं।

कहा- चुनाव लड़ना चाहता था, पर धमकी दी गई

पूर्व विधायक मंतूराम पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि, साल 2014 में वह कांग्रेस के प्रत्याशी थे। सारा माहौल उनके पक्ष में था। भाजपा प्रत्याशी की स्थिति बहुत खराब थी। उन्होंने कहा कि, उनके ऊपर करोड़ों के लेनदेन का आरोप लगा, लेकिन वास्तविकता में चुनाव लड़ना चाहता था। उस बीच में शासन की ओर से तत्कालीन एसपी राजेंद्र दास ने कॉल कर धमकी दी कि अगर अपना नाम वापस नहीं लिया तो कभी भी आपके ऊपर दुर्घटना घट सकती है, एनकाउंटर हो सकता है। मैंने मौत के डर से नाम वापस लिया।

अंतागढ़ उपचुनाव में लिया था नाम वापस

पूर्व विधायक मंतूराम पवार सीपीएम से एक बार और कांग्रेस से तीन बार चुनाव लड़ चुके हैं। इस दौरान एक बार 1998 में विधायक चुने गए थे। साल 2014 में कांग्रेस ने उन्हें अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। इसके चलते भाजपा को वाकओवर मिला था। इसके बाद प्रदेश ही नहीं पूरे देश में यह उप चुनाव चर्चा में आ गया था। इस घटना के बाद कांग्रेस ने मंतूराम पवार को पार्टी से निकाल दिया था।

कोर्ट में दिया था करोड़ों की डील को लेकर बयान

इसके बाद मंतूराम ने भाजपा की सदस्यता ले ली, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया। वहीं इस घटना के करीब चार माह बाद अंतागढ़ उपचुनाव को लेकर नया टेप भी सामने आया। टेपकांड में मंतूराम पवार को मुख्य आरोपी बनाया। इस दौरान उन्होंने कोर्ट में दिए अपने बयान में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, पूर्व सीएम अजीत जोगी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, अमित जोगी, फिरोज सिद्दीकी और अमीन मेनन के बीच नाम वापसी को लेकर करीब सात करोड़ रुपये में डील होने की बात कही।

विधानसभा चुनाव में मुझे टिकट मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं : लखमा

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने को है। चुनाव से पहले ही सभी पार्टियों के नेता वोटर्स के बीच पहुंच रहे हैं। इसी बीच मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है। लखमा ने अपने बयान में कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा कि नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि टिकट देने का फैसला गांधी परिवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे, छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के हाथों में हैं। मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूं। मैं एक छोटा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं।

पार्टी में दरी बिछाने और झंडा उठाने का काम

कवासी लखमा ने कहा कि मैं पार्टी के आदेश पर झंडा उठाने और दरी उठाने का काम करता हूं.पंडित नेहरु, राजीव गांधी, सोनिया गांधी,

राहुल गांधी बस्तर पहुंचे थे। लेकिन पहली बार कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी बीते दिनों बस्तर आई थी। उनके बस्तर प्रवास की जानकारी लगते ही बस्तर संभाग से भीड़ उमड़ पड़ी। जगदलपुर का ऐतिहासिक लालबाग मैदान लोगों से भर गया। दोपहर के 3:30 बजे प्रियंका गांधी की सभा खत्म हुआ। लेकिन 8:30 बजे तक जगदलपुर से लोगों से भरी गाड़ियां नहीं निकल पाई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सभा में बस्तरवासियों की भीड़ कितनी जुटी थी।

गांधी परिवार के कारण बस्तर का विकास

उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि यदि बस्तर के आदिवासी आज आगे बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे का कारण गांधी परिवार है। बस्तर का विकास गांधी परिवार ने किया है। तेंदू पत्ता तोड़ने का काम, जंगल जमीन का पट्टा, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आश्रम हॉस्टल नेहरू गांधी परिवार ने खोला है। अबूझमाड़ की वजह से बस्तर को जाना जाता है। बस्तर के अबूझमाड़ में आश्रम हॉस्टल खोलने का काम गांधी परिवार ने किया है। इससे पहले बस्तर के ट्राईबल मिनिस्टर केदार कश्यप ने 3000 स्कूलों को बंद किया लेकिन गांधी परिवार ने स्कूल आश्रम खोलकर बस्तर के आदिवासियों को आगे बढ़ाने का काम किया।

चरणदास महंत ने भवानी तिवारी को गमछा पहनाकर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई

- **भवानी तिवारी को मना पाने में नाकाम साबित हुई सक्ती भाजपा**

सक्ती। विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत के विधायक प्रतिनिधि नरेश गेवाड़ीन ने जबसे विधायक प्रतिनिधि की कमान संभाली है तब से लगातार सक्ती विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत के अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति से लेकर पंच सरपंच जनपद सदस्य सहित जनप्रतिनिधि गण भारी संख्या में इनके संपर्क में डॉ चरणदास महंत से रूबरू होकर अपनी समस्या बताते हैं और डॉ महंत इनकी समस्याओं को त्वरित निराकरण भी करते हैं,

आज 18 अप्रैल को विधायक प्रतिनिधि नरेश गेवाडीन के नेतृत्व में भवानी प्रसाद तिवारी को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलवाई, आपको बता दें भवानी प्रसाद तिवारी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जमीनी कार्यकर्ता से लेकर पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष एवं मंडल अध्यक्ष सहित विभिन्न पद पर रहने वाले भवानी प्रसाद तिवारी को आज 18 अप्रैल को विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने गमछा पहनाकर एवं नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष त्रिलोक चंद जायसवाल ने बेच

लगाकर विधिवत कांग्रेस की सदस्यता दिलाई और जिस तरह कांग्रेसमें भवानी तिवारी का प्रवेश होते ही भारतीय जनता पार्टी को सक्ती विधानसभा सहित पूरे जिले में बहुत बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सक्ती नगर पालिका से लेकर विधानसभा एवं लोकसभा में भवानी तिवारी के साथ हजारों की संख्या में समर्थक तत्पर रहते हैं। और विगत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर चल रहे भवानी तिवारी को मनाने में भाजपा के प्रदेश स्तर से लेकर स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों ने भवानी प्रसाद तिवारी को मनाने में नाकाम साबित हुई और आज नरेश गेवाडीन के नेतृत्व में डॉ चरणदास महंत के द्वारा कांग्रेस का गमछा पहन कर विधिवत सदस्यता लेकर कांग्रेश की सक्रिय राजनीति मैं जुट गए हैं। इस संबंध में जिला प्रतिनिधि गुलजार सिंह ठाकुर ने बताया कि सक्ती जिले में जिस तरह हमारे नेता डॉ चरणदास महंत अंतिम छोर के अंतिम कार्यकर्ता को भी सम्मान देते हैं तथा क्षेत्र में स्वास्थ्य सड़क पानी के साथ-साथ सर्वांगीण विकास कर रहे हैं ।

इस अवसर पर जिले के लाडले युवा नेता सूरज महंत, जिला प्रतिनिधि गुलजार सिंह ठाकुर, महंत समर्थक उगेंद्र अग्रवाल (पप्पू), नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष त्रिलोकचंद जयसवाल, कृषि उपज मंडी सक्ती अध्यक्ष रूप नारायण साहू, विधायक प्रतिनिधि एवं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष नरेश गेवाडीन, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष श्रीमती रीना गेवाडीन, वरिष्ठ कांग्रेस नेता घनश्याम पाण्डे, डभरा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रीतम अग्रवाल, जनपद सदस्य अशोक यादव, सरपंच संघ अध्यक्ष डमरु साहू, सरपंच श्याम राठौर, उत्तम लहरे, संजय सीदार, राजेंद्र साहू , जय प्रकाश सोंठी, पिंटू राठौर, रामनाथ पटेल, राजीव जायसवाल, अधिवक्ता राकेश महंत, अधिवक्ता रात राम पटेल, महंत समर्थक सुदेश शर्मा, भुरू अग्रवाल, कालू अग्रवाल, एक्सिस बैंक स्टॉप सहित भारी संख्या में कांग्रेस जन एवं नगरवासी उपस्थित थे।

नारायणपुर में तेंदूपत्ता फड़ मुंशियों ने चेतावनी के साथ खत्म की हड़ताल

नारायणपुर। नारायणपुर जिले में तेंदूपत्ता संघ के तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ये आंदोलनकारी प्रदेश सरकार से नाराज हैं। इनका आरोप है कि कांग्रेस की सरकार बनने से पहले चुनावी घोषणा पत्र में हर फड़मुंशी को 1 हजार रुपये प्रतिमाह देने वादा किया था लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार अपना वादा भूल गई। इसी के विरोध में पिछले तीन दिनों से तेंदूपत्ता संघ के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे थे। बुधवार को फड़मुंशियों ने अपना आंदोलन खत्म किया। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

सरकार को अपना वादा याद दिलाने के लिए किया प्रदर्शन

17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक धरना स्थल बखरूपारा में तेंदूपत्ता संघ के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार को अपने किए वादे को याद दिलाने के लिए फड़ मुंशी धरने पर बैठे। आंदोलनकारी फड़ मुंशियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले चुनावी घोषणा पत्र में प्रत्येक फड़मुंशी को एक हजार रुपया प्रतिमाह देने वादा किया गया था। सत्ता में आते ही सरकार ये वादा भूल गई। तेंदूपत्ता संध ने तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन

सौंपा है।

ये है मांग-फड़ मुंशियों ने बताया कि 10वीं 12वीं पास अनिवार्यता बताकर हर साल नए फड़ मुंशियों की भर्ती की जाती है। इसे खत्म करना चाहिए। गांव के ही अनुभवी युवकों को फड़मुंशी का काम देना चाहिए।

उग्र आंदोलन की चेतावनी

तेंदूपत्ता वनोपज में संग्रहण परिवार के बीमा काम, तेंदूपत्ता कार्ड बनाने में सर्वे का काम, सरकार की विभिन्न योजनाएं संचालित करने का काम, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार को फायदा दिलाने का काम तेंदूपत्ता फडमुंशी को दी जाती है। बिना मानदेय के पूरे साल फड़ मुंशियों से काम लिया जाता है। नाराज फड़ मुंशियों ने राज्य सरकार के चुनावी वादे को याद दिलाने के लिए तीन दिवसीय प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इन फड़ मुंशियों ने मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

प्रतिनियुक्ति कराने के मामले में धोखाधड़ी पति-पत्नी के खिलाफ अपराध दर्ज

कोरबा। पुलिस विभाग से परिवहन विभाग में प्रतिनियुक्ति कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले कोरबा जिले के एक कांग्रेस नेता और उनकी पत्नी के विरूद्ध सिटी कोतवाली बलौदाबाजार में जुर्म दर्ज कर लिया गया है।

पीड़ित प्रकाश सिंह पिता स्व.भागीरथी देशलहरे पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनका निवास ग्राम रिसदा थाना व जिला बलौदाबाजार है। जनवरी 2011 को अपने गाँव रिसदा में थे कि 25 जनवरी को भांजा चन्द्र कुमार टण्डन निवासी लटुआ घर आया था। साथ में एक पुरूष व महिला भी थे। भाँजा ने बताया कि ये रोशन बघेल और उनकी पत्नी हेमलता बघेल हैं जो मुझे शिक्षाकर्मी में नौकरी लगाने के लिए 2,60000 दो लाख साठ हजार रूपये लिये हैं। उसके बाद रोशन बघेल ने पीड़ित से कहा कि उसका परिवहन विभाग में प्रतिनियुक्ति करा सकता हूँ, पाँच लाख रूपये लगेगा। तब मैं पीड़ित ने 4 लाख पचहत्तर हजार रूपये दिया। उस समय भांजा चन्द्र कुमार टण्डन, पीड़ित का छोटा भाई गंगारतन व गांव का विष्णू बंजारे भी मौजूद थे। पैसा को रोशन बघेल ने पत्नी हेमलता बघेल को दिया जिसे वह बैग में रख ली। उसके बाद पीड़ित ने रोशन से पूछा कि अगर काम नहीं हुआ तो पैसा कैसे लौटाओगे? तब रौशन ने कहा कि 5-6 महीना लगेगा, अगर विश्वास नहीं है तो चेक रख लो इतना कहकर अपने बैग से एक चेकबुक निकाला जो यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कोरबा का चेक क्रमांक 410938, खाता क्रमांक 4168010614290 का था, उस एक चेक को 6 महीने बाद की तारीख 30.07.2011 रकम 4 लाख पचहत्तर हजार रूपये भरकर पीड़ित के नाम का दिया और चले गये। 6 महीने बाद जब पीड़ित का परिवहन विभाग में प्रतिनियुक्ति नहीं हुआ तो रोशन से सम्पर्क किया तब उसने कहा, कुछ दिन और लगेगा। उसके बाद से कई बार सम्पर्क किया किन्तु रोशन का मोबाईल बंद रहता था। फिर पीड़ित उसके गाँव गुरसिया आया तो वहाँ भी नही मिला। इस तरह रूपये ऐंठकर धोखाधड़ी करने वाले रोशन बघेल व हेमलता बघेल ग्राम गुरसिया, थाना बांगो के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के आवेदन पर जांच उपरांत 14 अप्रैल को धारा 420,34 भादवि का जुर्म दर्ज कर लिया गया।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

आईईडी निष्क्रिय करने की कोशिश में पुलिसकर्मी घायल

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बृहस्पतिवार को माओवादियों द्वारा लगाए गए संदिग्ध आईईडी में विस्फोट होने से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पिछले 22 दिनों में बीजापुर जिले में इस तरह की यह तीसरी घटना है। एक अधिकारी ने बताया कि ताजा घटना नेलासनर पुलिस थाना क्षेत्र के बंगापाल गांव के पास उस समय हुई जब पुलिस की एक टीम इलाके में दबिश देने के लिए अभियान चला रही थी। उन्होंने बताया कि गश्त के दौरान टीम को बंगापाल से तीन किलोमीटर आगे माओवादियों द्वारा लगाए गए एक आईईडी का पता चला। जब आईईडी को निष्क्रिय किया जा रहा था तो उसमें विस्फोट हो गया। जिससे जवान सीताराम कुडियाम घायल हो गया। घायल जवान को एक स्थानीय अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया और प्रारंभिक उपचार के बाद, उसे आगे की दवा के लिए दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। इससे पहले 17 अप्रैल को बड़े तुंगली गांव के पास इसी तरह की घटना में जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) का एक जवान घायल हो गया था।

मुंगेली एसडीएम ने किया नशामुक्ति केन्द्र का निरीक्षण

मुंगेली। कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर मुंगेली अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री आकांक्षा शिक्षा खलखो ने ग्राम सुरीघाट में स्थित 15 बिस्तरीय एकीकृत पुनर्वास (नशामुक्ति) केन्द्र का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां साफ-सफाई, पंजीकृत रजिस्टर, बिजली, पानी और कर्मचारियों की संख्या के बारे में जानकारी ली और केन्द्र के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए। संस्था संचालक कमल यादव ने नशामुक्ति केन्द्र में नशा से लिप्त लोगों को प्रवेश नियम की प्रक्रिया, नशापीड़ित व्यक्तियों का नि:शुल्क ईलाज, भोजन एवं आवास की व्यवस्था आदि के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ शबरी सेवा संस्थान बछेरा द्वारा नशामुक्ति सह एकीकृत पुनर्वास केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। जहां नशापीड़ित व्यक्तियों का नि:शुल्क ईलाज, भोजन एवं आवास की व्यवस्था उपलब्ध है। निरीक्षण के दौरान समाज कल्याण विभाग से अशोक जायसवाल, नशामुक्ति केन्द्र के प्रबंधक नीलकंठ टोण्डे आदि उपस्थित थे।

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बैंक के बैंक मैनेजर को 420 के मामले में भेजा गया जेल

कोरबा। प्रार्थी राजकुमार पैकरा पिता स्व.गुलबदन सिंह पैकरा उम्र 66 वर्ष सा.भदरापारा पाडीमार बालको थाना बालको नगर जिला कोरबा छग के पुत्र राकेश कुमार पैकरा का सड़क दुर्घटना से मृत्यु होने पर मृतक के परिजनो को बीमा कंपनी द्वारा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बीमा के माध्यम 50 लाख रुपये की बीमा राशि दिया गया था। उक्त बीमा राशि में से करीबन 18 लाख रूपये को आरोपी बैंक मैनेजर दिलीप तिवारी द्वारा प्रार्थी के बहु निशा कंवर एवं प्रार्थी का धोखे से हस्ताक्षर करा कर छल पूर्वक 18,00000 रूपये आहरण कर आर्थिक क्षति पहुंचाने संबंधी लिखित शिकायत पत्र पर आरोपी के विरूद्ध दिनाँक 31/03/23 को अपराध क्रमांक 232/2023 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। 19 अप्रैल को आरोपी का रजगामार क्षेत्र पिकनिक मनाने जाने की सूचना पर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी को पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

मैदान बना डंपिंग यार्ड, बदबू और धुएं से लोग परेशान

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा का शांति नगर कचरे के चलते अशांत है। नैला के वार्ड-25 में खाली पड़े मैदान को कचरा डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। शहर का कचरा हो या फिर मरे हुए जानवर, सब यहीं फेंके जा रहे हैं। जब कचरा बढ़ता है तो नगर पालिक के कर्मचारी उसमें आग लगा देते हैं। जिसके चलते बदबू और धुएं से लोग परेशान हैं। खास बात यह है कि क्षेत्र में बच्चों के खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है, लेकिन जब कोई बड़ा नेता आता है, तो इसे साफ जरूर कर दिया जाता है। लोगों ने शिकायत भी की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। दरअसल, नगर पालिका के वार्ड- 25 शांति नगर के खाली मैदान में पिछले 15 से 20 सालों से शहर का कचरा डंप किया जा रहा है। यहां आसपास शासकीय दफ्तर और कॉलेज है। इसके बावजूद कचरे का निपटारा नहीं किया जाता। इसके चलते वार्ड में रहने वालों के साथ ही आसपास के इलाके के लोग भी परेशान हैं। कई बार वार्ड के लोग इसे लेकर विरोध भी जता चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

मकान में भीषण आग लगने से जल गया सारा सामान

बलौदाबाजार। बीती रात करही बाजार के बस स्टैंड के समीप एक घर मे भीषण आग लगने से हडकंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में सब कुछ जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना पर करही पुलिस, बलौदाबाजार दमकल विभाग व न्यूको सीमेंट संयंत्र से फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंची और देर रात आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के मुताबिक यह आग नंदु पटेल के घर लगी थी. जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया। जनहानि की कोई सूचना नहीं है। लेकिन घर के सारे सामान जल गए हैं। बलौदाबाजार जिले में यह एक ही दिन में दूसरी घटना है। पहली घटना ग्राम छेरकापुर में हुई थी, जिस पर भी बलौदाबाजार दमकल की टीम ने काबू पाया। देर रात करही बाजार पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी, इसका कारण अज्ञात है। आग बड़ी तेजी से फैली है, जिसकी लपटें दूर से दिखाई दे रही थीं। करही चौकी पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।

3 राईस मिलों में लापरवाही बरतने पर की गई छापामार कार्यवाही

मुंगेली। जिले में कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार धान उठाव करने के पश्चात कस्टम मिलिंग का चावल समय पर भारतीय खाद्य निगम में जमा करने में लापरवाही बरतने वाले राईस मिलरों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में जिला खाद्य अधिकारी श्री देवेन्द्र बग्गा एवं सहायक खाद्य अधिकारी श्रीमती ज्योति मिश्रा और खाद्य निरीक्षक श्रीमती शिखा झा द्वारा मे. हाजी राईस मिल, मे. उपलेटा ट्रेडर्स राईस मिल और मे. हाजी परबाइलिंग धरमपुरा में दबिश दी गई तथा उनके द्वारा धान एवं चावल का भौतिक सत्यापन किया गया। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि मे. हाजी राईस मिल द्वारा कस्टम मिलिंग वर्ष 2022-23 हेतु कुल 60 हजार क्विंटल धान उठाव किया गया है। जिसकी कुल चावल 40538 क्विंटल नागरिक आपूर्ति निगम में जमा किया जाना था, किंतु आज दिनांक तक मात्र 24 हजार 345 क्विंटल चावल ही जमा किया गया है। शासन को 16192 क्विंटल

चावल देना शेष है। उन्होंने बताया कि मे. हाजी राईस मिल धरमपुरा में तौल कर रखे 233 क्विंटल अनाधिकृत धान को जब्त कर कार्यवाही की गई है।

इसी प्रकार मे. उपलेटा ट्रेडर्स राईस मिल द्वारा कस्टम मिलिंग वर्ष 2022-23 हेतु कुल 72000 क्विंटल धान उठाव किया गया है। जिसकी कुल चावल 48624.71 क्विंटल नागरिक आपूर्ति निगम में जमा किया जाना था, किंतु आज दिनांक तक मात्र 29853.21 क्विंटल चावल ही जमा किया गया है। शासन को 18771.05 क्विंटल चावल देना शेष है। उन्होंने बताया कि मे. उपलेटा ट्रेडर्स मिल धरमपुरा में तौल कर रखे 282 क्विंटल अनाधिकृत धान जब्त कर कार्यवाही की गई है। इसी तरह मे. हाजी परबाइलिंग धरमपुरा द्वारा भारतीय खाद्य निगम में आज दिनांक तक लक्ष्य के अनुरूप चावल जमा नही करने पर खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच की गई, जिसमें भौतिक सत्यापन में 90 क्विंटल धान अधिक पाये जाने पर धान जब्त कर कार्यवाही की गई है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि पूर्व में भी कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले के 05 उसना मिलर्स को भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करने में लापरवाही बरतने के कारण नोटिस जारी किया गया था। भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करने में लापरवाही करने वाले मिलरों के विरूद्ध आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।

रामविचार नेताम ने ली शक्ति केंद्रों की बैठक

मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-सोनहत। विधान सभा की शक्ति केंद्रो की बैठक में मुख्य वक्ता राम विचार नेताम् पूर्व गृह मंत्री छत्तीगढ शासन व श्रीमती चंपा देवी पावले, रितेश गुप्ता व प्रदेश के पदाधिकारी जिला के पदाधिकारी मंडल के अध्यक्ष ,महामंत्री, शक्ति केंद्र के प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजक सहस्योजक की उपस्थिति में आयोजित की गई. बैठक की शुरुआत भारत माता, पितृ पुरुष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पित करके हुई। अपने उद्बोधन में पूर्व संसदीय सचिव चंपा देवी पावले ने समस्त अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं का अभिवादन

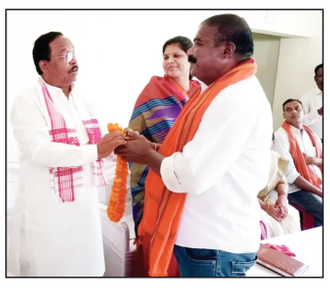

किया। उन्होंने कहा पार्टी की गतिविधियों को शक्ति केन्द्रों तक पहुँचाना है। शक्ति केंद्र और बूथों को मजबूत करना है। आप सभी अविलंब शक्ति केंद्रों की बैठक लें तथा वस्तुस्थिति से अवगत? करायें। समस्त शक्ति केंद्रों की आगामी रूप रेखा तय करें तथा शक्ति केंद्रों का सुदृढ़ीकरण करना जारी रखें। समस्त जिले के पदाधिकारी, मंडलों के अध्यक्ष, मंडलों के प्रभारी एवं प्रकोष्ठों के संयोजक आगामी कार्यक्रमों को संकल्प के साथ सम्पन्न करायें।

रितेश गुप्ता ने कहा आज हम महत्वपूर्ण कामकाजी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इसी प्रकार ऐसी बैठकें शक्ति केंद्रों तथा बूथ केंद्रों तक आयोजित होंगी। आगामी समय में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होना है, हम चुनावी समर के मुहाने पर खड़े हैं। आने वाले समय में हमारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली हैं। कार्यक्रमो की रूपरेखा उपर से तय होकर आती है। हमें जो भी निर्देश प्राप्त हों, उनको पूरी निष्ठा के साथ पूरा करना है।

मुख्य वक्ता राम विचार नेताम ने अपने उद्बोधन में कहा कि भाजपा सेवा? ही संगठन की अवधारणा पर काम करती है। पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रहित में लगातार काम करते चले जा रहे हैं।

आपदा की स्थिति में भाजपा कार्यकर्ता सेवा में अग्रसर रहे हैं। उन्होंने घर-घर बिजली, सड़कों का जाल, पीने का शुद्ध पानी हर घर तक पहुंचाए जाने की बात कहते हुए शक्ति केंद्र में सभी बूथों को मजबूत करने को लक्ष्य बनाने कहा। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता जमुना पांडे, संजय सिंह,नगर पंचायत खोगापानी अध्यक्ष धीरेन्द्र विश्वकर्मा, नगर पंचायत नई लेदरी अध्यक्ष सरोज यादव,इंदु पनेरिया समेत पार्टी कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद रहे।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

शरद पवार से मुंबई में गौतम अडानी ने की मुलाकात

मुंबई। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने गुरुवार को एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मुंबई में मुलाकात की। सामने आई जानकारी के अनुसार गौतम अडानी खुद पवार के घर पहुंचे थे और दोनों के बीच दो घंटे बैठक चली। यह मुलाकात तब हुई है जब अडानी के खिलाफ जांच को लेकर विपक्ष लगातार मांग उठा रहा है। कांग्रेस इस मामले में सबसे मुखर है। हालांकि, शरद पवार ने हाल में कहा था कि वह अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए जेपीसी से जांच कराने की कुछ विपक्षी पार्टियों की मांग से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा था कि वह अडानी को लेकर भाजपा विरोधी पार्टियों की मांग से हालांकि सहमत नहीं है, लेकिन वह विपक्षी दलों की एकता की खातिर उनके रुख के खिलाफ नहीं जाएंगे। पवार ने कहा था कि जेपीसी का गठन किया जाता है तो संसद में सत्तारूढ़ भाजपा के संख्याबल को देखते हुए उसमें (समिति में) उसका बहुमत होगा और इससे इस तरह की जांच के परिणाम पर संदेह उत्पन्न होगा।

कांग्रेस का संगठन कमजोर है : दिग्विजय सिंह

भोपाल। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी को आइना दिखा दिया है। दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि पोलिंग के दिन भी कांग्रेस का इलेक्शन मैनेजमेंट कमजोर रहता है। दरअसल, मध्यप्रदेश के सीहोर में दिग्विजय सिंह पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस का संगठन कमजोर रहता है। कांग्रेस नेता ने साफ तौर पर कहा कि हमारी पार्टी का जैसा संगठन होना चाहिए, वैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव वाले दिन भी पोलिंग मैनेजमेंट में भारी कमी रहती है, जिस तरह की तैयारी पहले से होनी चाहिए वैसी नहीं होती है। इसके साथ ही दिग्विजय ने यह भी कह दिया कि जनता तो हमें वोट देना चाहती हैं लेकिन हमारा संगठन ही कमजोर है। दिग्विजय सिंह ने अपने वक्तव्य में यह नहीं बताया कि पार्टी का संगठन के आधार पर उन्हें कमजोर नजर आता है।

सचिन पायलट को रंधावा की नसीहत, दिए एक्शन के संकेत

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पूर्व डिप्टी सचिन पायलट के बीच सत्ता को लेकर जारी खींचतान के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कड़ा संदेश दिया कि कोई भी नेता पार्टी से ऊपर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पायलट को इस मुद्दे पर एक दिन का उपवास करने के बजाय राजस्थान विधानसभा में बहस के दौरान पिछली भाजपा सरकार द्वारा कथित भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की मांग उठानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने वालों और इसके लिए समस्या पैदा करने वालों को गंभीरता से देख रहे हैं। विधानसभा से बड़ा कोई मंच नहीं होता क्योंकि विपक्ष था, कांग्रेस विधायक और मुख्यमंत्री वहां थे। हमारी सरकार ने आज तक क्या किया है, इसके बारे में उन्हें विधानसभा में अपनी बात उठानी चाहिए थी। मुख्यमंत्री को जवाब देना होता।

कर्नाटक चुनाव में औवैसी की एंट्री से बढ़ी कांग्रेस की मुश्किलें

बेंगलुरु। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। ऐसे में जहां भाजपा अपनी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस उत्तरी कर्नाटक में अपने प्रदर्शन में सुधार कर सीटों की संख्या में इजाफा करना चाहती है। तो वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। राजनीतिक दलों की उथल-पुथल के बीच अब ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की कर्नाटक चुनाव में एंट्री से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एआईएमआईएम ने कर्नाटक के विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। पार्टी की ओर से लिस्ट में तीन नामों की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि अन्य नामों को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एआईएमआईएम, जेडीएस के साथ गठबंधन के फिराक में लगी है।

कर्नाटक में ईश्वरप्पा के बेटे को भाजपा ने नहीं दिया टिकट

बेंगलुरु। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की चौथी एवं अंतिम सूची जारी कर दी है। इस सूची में 222 निर्वाचन क्षेत्रों के अलावा शेष रह गये दो निर्वाचन क्षेत्रों शिमोगा और मानवी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। भाजपा ने शिमोगा से पांच बार के विधायक रहे केएस ईश्वरप्पा के बेटे केई कांतेश को टिकट न देकर चन्नबसप्पा को मैदान में उतारा है। दरअसल भाजपा में शिमोगा विधानसभा क्षेत्र को लेकर काफी गहमागहमी थी। उसके दो प्रमुख कारण थे। पहला तो यह कि यहां से मौजूदा भाजपा विधायक केएस ईश्वरप्पा ने हाल ही में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चिट्ठी लिखकर चुनावी सन्यास का ऐलान किया था। उसके बाद से कयास लगाये जा रहे थे कि ईश्वरप्पा ने अपने बेटे केई कांतेश को राजनीति में आगे बढ़ाने के आशय से चुनावी राजनीति से किनारा किया है लेकिन भाजपा ने ईश्वरप्पा के अरमानों पर पानी फेर दिया है।

राहुल की अर्जी सूरत कोर्ट से हुई खारिज

नईदिल्ली। सूरत सेशंस कोर्ट ने 20 अप्रैल को मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस नेता ने 'मोदी उपनाम' वाले केस में उनकी सजा पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। सूरत अदालत ने राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा की अदालत ने राहुल गांधी के आवेदन पर फैसला 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट के इस फैसले के चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी चली गई थी। अब सेशंस कोर्ट से भी कांग्रेस नेता को निराशा हाथ लगी है । अब राहत के लिए राहुल गांधी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। राहुल को आपराधिक मानहानि के इस मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाये जाने के एक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल की अपील लंबित रहने के बीच फैसला सुरक्षित रखा गया। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से सांसद बने थे। गत 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया। राहुल ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ तीन अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया। उनके वकीलों ने दो आवेदन भी दाखिल किये जिनमें एक सजा पर रोक के लिए और दूसरा अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराये जाने पर स्थगन के लिए था।

अदालत ने राहुल को जमानत देते हुए शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किये थे। उसने पिछले गुरुवार

को दोनों पक्षों को सुना और फैसला 20 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग जारी रखेंगे : कांग्रेस

कांग्रेस ने अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात की एक सत्र अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग जारी रखेगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, कानून के तहत जो भी विकल्प हमारे लिए उपलब्ध होंगे, हम उन सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेंगे। गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने 'मोदी उपनाम' वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा की अदालत ने राहुल को आपराधिक मानहानि के इस मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाये जाने के एक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अर्जी आज खारिज कर दी।

महबूबी मुफ्ती ने कहा- भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गुजरात की एक अदालत द्वारा मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज किए जाने के बाद गुरुवार को भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इस मुल्क के लिए आज काला दिन है क्योंकि विपक्षी नेता के साथ इस किस्म का व्यवहार किया जाए तो मुझे लगता है कि कही न कही बीजेपी इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाना चाहती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो यहां की संविधान को खत्म करके अपने एजेंडे पर चलाना चाहती है वो बीजेपी राज चलाना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मानहानि मामले में जो फैसला आया है वो विपक्ष को एक संदेश है।

इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। महबूबी मफ्ती ने कहा कि भाजपा विपक्ष के सबसे प्रमुख चेहरे को परेशान कर रही है और किसी भी और सभी प्रकार की आलोचनाओं का अपराधीकरण करने से भाजपा राष्ट्र की स्थापना के उनके असली डिजाइन का पता चलता है। उन्होंने कहा कि भारत को बनाना रिपब्लिक में बदलने के लिए लोकतंत्र को नष्ट किया जा रहा है। एक पार्टी के वर्चस्व के पक्ष में कानूनों और एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी आखिरी उम्मीद न्यायपालिका से है। दुख की बात है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से न्याय में देरी हो रही है और कैसे चुनिंदा तरीके से सजा दी जा रही है।

पूर्व सीएम ने कहा कि अदालतें अनुच्छेद 370, बिलकिस बानो और सीएए पर अपने पैर खींचती हैं लेकिन कथित मानहानि के मामलों को फास्ट ट्रैक करती हैं। जम्मू-कश्मीर बीजेपी के भयावह एकतरफा फैसलों का खामियाजा सबसे पहले भुगतने वाला था। आज, वह आग पूरे भारत में भड़क रही है और आग की लपटों में घिरने का खतरा है। आशा है कि इस देश के लोग स्थिति की गंभीरता को समझेंगे और महसूस करेंगे कि इसे रोकने की शक्ति उनके पास है।

कानून सबके लिए एक, फैसले से गांधी परिवार का घमंड टूटा : भाजपा

नईदिल्ली। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज को गाली दिया था। उन्होंने कहा कि गुरुवार को कोर्ट के फैसले को लेकर ओबीसी समाज में खुशी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह आम जनता की जीत है और गांधी परिवार का घमंड टूटा है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार में घमंड है। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी पर मानहानि के मामले में उनकी सजा को रोकने के अनुरोध को खारिज करना भारत के आम लोगों के लिए जीत का प्रतीक है, यह पिछड़े वर्गों के लिए उत्सव का क्षण है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट से जो सजा मिली थी, उस सजा पर सूरत की अपीलीयट कोर्ट से रोक लगेगी। इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही थीं। आज जो सूरत की अपीलीयट कोर्ट का फैसला आया है, उससे पूरे देश में खुशी का माहौल है। पात्रा ने कहा कि जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था और उन्हें गाली देने का काम किया था... और ये सब करके गांधी परिवार को लगता था कि वो बचकर निकल जाएंगे, वह नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला गांधी परिवार के मुंह पर तमाचा है। आज सूरत की कोर्ट से सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने कहा कि आज के इस फैसले से एक बात स्पष्ट होती है कि इस देश में संविधान का राज है, परिवार का राज नहीं है और किसी भी परिवार के लिए preferential treatment नहीं हो सकता है।

भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया

बौद्ध शिक्षा द्वारा विश्व की सभी समस्याओं का हो सकता है समाधान: मोदी

नईदिल्ली। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि बौद्ध शिक्षा द्वारा आधुनिक विश्व की सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बुद्ध का मार्ग भविष्य और स्थिरता का मार्ग है। उन्होंने कहा कि बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़ कर एक बोध हैं, बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच हैं, बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना हैं और बुद्ध की ये चेतना चिरंतर है निरंतर है... यह सोच शाश्वत है, ये बोध अविस्मरणीय है। इसलिए आज जितने भी अलग-अलग देशों से, भौगोलिक-सांस्कृतिक परिवेश से लोग यहां एक साथ उपस्थित हैं। यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वयं के लिए एक प्रकाश बनो, भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया। आज, यह शिक्षण इतने सारे सवालों के जवाबों को समेटे हुए है। भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया, यह मैंने गर्व से संयुक्त राष्ट्र में कहा था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है, जब भारत अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अमृत काल में विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है। भारत ने न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए संकल्प लिया है। मोदी ने कहा कि भारत ने इतने सारे क्षेत्रों में अपना पहला स्थान हासिल किया है, और उसने भगवान बुद्ध से उसी के लिए महान प्रेरणा प्राप्त की है। बुद्ध की शिक्षाओं में सिद्धांत, अभ्यास और प्राप्ति का मार्ग शामिल था; भारत पिछले 9 वर्षों में बुद्ध

द्वारा बताए गए मार्गों पर चलकर बड़ी प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि बुद्ध का मार्ग है- परियक्ति, पटिपत्ति और पटिवेध। यानी Theory, Practice and Realization. पिछले 9 वर्षों में भारत इन तीनों ही बिन्दुओं पर तेजी से आगे बढ़ा है।

मोदी ने कहा कि हमें विश्व को सुखी बनाना है तो स्व से निकलकर संसार, संकुचित सोच को त्यागकर, समग्रता का ये बुद्ध मंत्र ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का हर काम किसी न किसी रूप में धरती को प्रभावित कर रहा है। हमारी लाइफस्टाइल चाहे जो हो, हर बात का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। हर व्यक्ति जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ भी सकता है। उन्होंने कहा कि अगर लोग जागरूक होकर प्रयास करें तो इस बड़ी समस्या से निपटा जा सकता है। यही तो बुद्ध का मार्ग है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बुद्ध का मार्ग भविष्य का मार्ग है, sustainability का मार्ग है। अगर विश्व, बुद्ध की सीखों पर चला होता तो क्लाइमेट चेंज जैसा संकट भी हमारे सामने नहीं आता। ये संकट इसलिए आया क्योंकि पिछली शताब्दी में कुछ देशों ने दूसरों के बारे में, आने वाली पीढ़ियों के बारे में नहीं सोचा।

खेल
प्रमुख समाचार

स्टोक्स के फिट होने से चेन्नई की सनराइजर्स के खिलाफ उम्मीदें बढ़ीं

चेन्नई। चार बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की टीम शुक्रवार को यहां जब इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना करेगी तो उसे उम्मीद रहेगी कि उसके स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स आखिरकार फिट होकर मैदान पर उतरेंगे। पांव की चोट के कारण स्टोक्स पिछले तीन मैचों में नहीं खेल पाए थे लेकिन चेन्नई के लिए यह राहत की बात है कि अब वह फिट हैं और चयन के लिए उपलब्ध हैं। स्टोक्स ने बुधवार को अभ्यास सत्र में भी हिस्सा लिया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) पर करीबी जीत दर्ज करने के बाद चेन्नई की टीम अपने घरेलू मैदान पर लौट रही है और ऐसे में इंग्लैंड के कप्तान की वापसी से उसे और मजबूती मिलेगी।

उसके प्रतिद्वंदी सनराइजर्स को पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। डेवोन कॉनवे और रुतुराज गायकवाड़ की सलामी जोड़ी के शानदार प्रदर्शन तथा शिवम दुबे की आक्रामक पारी की मदद से चेन्नई ने पिछले मैच में बड़ा स्कोर खड़ा किया था। अजिंक्य रहाणे जिस तरह से बेफिक्र होकर आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, उससे चेन्नई को मजबूती मिली है लेकिन उसके अन्य बल्लेबाज खास योगदान नहीं दे पाए हैं। चेन्नई के प्रमुख बल्लेबाज जहां अपना जलवा दिखा रहे हैं वहीं उसके गेंदबाज रन प्रवाह रोकने में नाकाम रहे हैं। चेन्नई का क्षेत्ररक्षण भी अच्छा नहीं रहा है। श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना ने आरसीबी के खिलाफ प्रभावशाली प्रदर्शन किया लेकिन अन्य गेंदबाजों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है हालांकि प्रत्येक मैच के बाद तुषार देशपांडे के प्रदर्शन में सुधार हो रहा है। चेन्नई को अगर सनराइजर्स के बल्लेबाजों पर लगाम कसनी है तो उसके तीनों स्पिनरों महेश तीक्ष्णा, रविंद्र जडेजा और मोइन अली को और बेहतर प्रदर्शन करना होगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

65 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स

नईदिल्ली। ग्लोबल मार्केट से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच गुरुवार के कारोबार में शेयर बाजार में लगातार तीन दिन से जारी गिरावट पर ब्रेक लग गया। आज के कारोबार में शेयर बाजार में आज हल्की तेजी देखी गई। घरेलू शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 65 अंक मजबूत हुआ। वहीं, निफ्टी 6 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 17,600 के ऊपर बना रहा। कारोबार समाप्त होने से पहले ऊर्जा और टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बाजार में तेजी लौटी। कारोबारियों के अनुसार, हालांकि विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी जारी रहने के बीच निवेशकों की चिंता तथा जोखिम से बचने की धारणा का बाजार पर असर है। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 64.55 अंक यानी 0.11 फीसदी मजबूत होकर 59,632.35 अंक पर बंद हुआ।

भारत को मिला ऐपल का दूसरा रिटेल स्टोर

नईदिल्ली। आईफोन बनाने वाली दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी ऐपल ने गुरुवार को अपना एक और रिटेल स्टोर दिल्ली में भी खोल दिया है। बता दें कि मुंबई के बाद यह ऐपल का दूसरा स्टोर है जो भारत में खोला गया है। इस नए स्टोर का उद्घाटन सीईओ टिम कुक ने गुरुवार को सुबह 10 बजे नई दिल्ली के साकेत में किया है। बता दें कि टिम कुक 7 साल बाद भारत यात्रा के लिए आए हुएं हैं। इस दौरान उन्होंने भारत में ऐपल के दूसरा ऑफिशियल रिटेल स्टोर की ओपनिंग की है। आईफोन लवर्स काफी समय से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। ओपनिंग से पहले ही दिल्ली के साकेत स्थित सेलेक्ट सिटीवॉक मॉल के बाहर यूजर्स की भीड़ लगी हुई थी। 'एप्पल साकेत' नाम के इस स्टोर का डिजाइन दिल्ली के पुराने दरवाजों से प्रेरित है। हालांकि आकार में यह मुंबई के स्टोर से छोटा है।

नेटफ्लिक्स यूजर्स के लिए मंथली प्लान होंगे सस्ते

नईदिल्ली। ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स लोगों को पासवर्ड साझा करने के लिए मोटिवेट करने को लेकर अपने सस्ते ऐड-सपोर्ट प्लान के साथ अधिक फीचर्स और बेहतर रिज़ॉल्यूशन पेश करने की योजना बना रहा है। पिछले साल नेटफ्लिक्स यूजर्स की संख्या में बड़ी गिरावट आई थी। इससे निराश कंपनी ने यूजर्स को बढ़ाने के लिए नए-नए उपाय अपनाये थे। अब कंपनी की तरफ से सस्ते में नेटफ्लिक्स प्लान लॉन्च किए जा सकते हैं। साथ ही सस्ते ऐड सपोर्ट प्लान लॉन्च किए जा सकते हैं। स्ट्रीमिंग कंपनी ने इन्वेस्टर्स को भेजे लेटर में बताया कि ऐड सपोर्टिड प्लान सब्सक्राइबर्स को उनके प्लान के बदले बेहतर वैल्यू प्रदान करेगा। ओटीटी मंच इस सस्ते प्लान में दो अकाउंट ऐड करने की सुविधा देगा। मतलब पहले जहां एक सस्ते ऐड सपोर्टेड प्लान में एक वक्त में एक यूजर्स नेटफ्लिक्स देख सकता था। वहीं, अब दो यूजर्स नेटफ्लिक्स का एक वक्त में इस्तेमाल कर पाएंगे।

कोयम्बटूर में 20 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी टाटा

नईदिल्ली। बिजली कंपनी टाटा पावर ने कोयम्बटूर में 20 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कोयंबटूर नगर निगम के साथ भागीदारी की है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। तमिलनाडु में इन ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के बाद यहां टाटा पावर द्वारा स्थापित ईवी चार्जिंग स्टेशन की कुल संख्या बढ़कर 116 हो जायेगी। यह चार्जिंग स्टेशन, कोयम्बटूर और आसपास के शहरों में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को चौबीस घंटे और सातों दिन चार्जिंग सेवा के साथ-साथ रखरखाव सुविधा उपलब्ध कराएंगे। टाटा पावर में व्यवसाय विकास (ईवी चार्जिंग) के प्रमुख वीरेंद्र गोयल ने कहा, ''कोयम्बटूर नगर निगम समेत अन्य निकायों के साथ साझेदारी करके हम भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना आसान बनाना चाहते हैं। हमारा प्रयास है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन उपयोगकर्ताओं की आसान पहुंच में हों।''

मजबूत डिजिटल ढांचे की अहमियत

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

इन दिनों पूरी दुनिया में हाल में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) द्वारा प्रकाशित वर्किंग पेपर स्टैकिंग अप द बेनिफिट्स लेसंस फ्रॉम इंडियाज डिजिटल जर्नी को पढ़ा जा रहा है। इसमें कहा गया है कि भारत ने अपने सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए एक विश्वस्तरीय बहुआयामी मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (डीपीआई) विकसित किया है। यह अन्य देशों के लिए सबक है, जो अपने डिजिटल बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है।

इस वर्किंग पेपर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गयी प्रधानमंत्री जन धन योजना की सराहना की गयी है और कहा गया है कि मजबूत डिजिटल नीतियों से भारत में प्रतिस्पर्धी, खुला और किफायती दूरसंचार बाजार बना है तथा मोबाइल डेटा की लागत में 90 फीसदी की कमी से डेटा इस्तेमाल में उछाल आया है। नोटबंदी से यूपीआई समेत भुगतान के अन्य तरीकों का अधिक इस्तेमाल हुआ है।

डिजिटलीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में मदद की है और आधार ने लीकेज को कम करते हुए लाभार्थियों को भुगतान के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) में मदद की है। इस डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग कर भारत कोविड महामारी के दौरान गरीब परिवारों के एक बड़े हिस्से को जल्दी सहायता प्रदान करने में सक्षम बना रहा है। मार्च 2021 तक डिजिटल सुधारों के कारण व्यय में जीडीपी का लगभग 1.1 फीसदी बचाया गया है।

इस समय देश में 47.8 करोड़ से अधिक

जन धन खातों (जे), 134 करोड़ से अधिक आधार कार्ड (ए) और 118 करोड़ से अधिक मोबाइल उपभोक्ताओं (एम) के तीन आयामी जैम से आम आदमी डिजिटल दुनिया से जुड़ गया है। वर्ष 2014 से लागू डीबीटी योजना एक वरदान की तरह दिख रही है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने डीबीटी के जरिये करीब 27 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि सीधे लाभान्वितों के खातों तक पहुंचायी है।

बैंक खातों में डीबीटी से सीधे सब्सिडी जमा कराने से करीब सवा दो लाख करोड़ रुपये बिचौलियों के हाथों में जाने से बचाये गये हैं। भारत ने पिछले एक दशक में मजबूत डिजिटल ढांचे से डिजिटलीकरण में एक लंबा सफर तय कर लिया है।

जहां केंद्र और राज्य सरकारों की 450 से अधिक योजनाओं का फायदा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने में बड़ी कामयाबी मिली है, वहीं लोगों की सुविधाएं बढ़ी है। देश में सौ से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। छोटे उद्योग-कारोबार के लिए सरल ऋण और रोजगार सृजन हेतु अप्रैल 2015 को डिजिटल रूप से लागू प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मार्च 2023 तक 40.82 करोड़ लोन खातों में 23.2 लाख करोड़ रुपये भेजे गये हैं।

जनवरी 2023 से शुरू डिजिटल राशन प्रणाली से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को हर महीने खाद्यान्न निशुल्क प्रदान किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक 27 फरवरी 2023 तक किसान सम्मान निधि योजना के तहत 13 किस्तों में 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किये जा चुके हैं। यह अभियान दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। देश में बढ़ते डिजिटलीकरण ने रोजगार के नये डिजिटल अवसर भी पैदा किये हैं। कोरोना की चुनौतियों के बीच भारत के आईटी सेक्टर द्वारा समय पर दी गयीं गुणवत्तापूर्ण सेवाओं से वैश्विक उद्योग-कारोबार इकाइयों का भारत की आईटी कंपनियों पर भरोसा बढ़ा है। डिजिटल इकोनॉमी के तहत कॉमर्स, बैंकिंग, मार्केटिंग, ट्रांजेक्शन, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, आईटी, टूरिज्म, रिटेल ट्रेड, हॉस्पिटेलिटी आदि क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के चमकीले मौके बढ़ते जा रहे हैं।

यूपी में करवट बदलता मुस्लिम मतदाता

उमेश चतुर्वेदी

उत्तर प्रदेश के तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों की मौजूदा राजनीति इन दिनों अतीक और उसके भाई की हत्या की अचंभित कर देने वाली घटना के ही इर्द-गिर्द घूम रही है। यूं तो समूचा विपक्ष पुलिस कस्टडी में हुई हत्या के लिए राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल उठा रहा है। लेकिन इसमें सबसे आगे समाजवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में अपने उभार के दिनों से ही समाजवादी पार्टी राज्य के मुसलमानों की पसंदीदा पार्टी रही है। राज्य का मुसलमान और यादव मतदाता उसका आधार वोटबैंक रहा है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या को बाकी दलों की तुलना में ज्यादा उठा रही है। वैसे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता बहुजन समाज पार्टी की सदस्य बन चुकी थी। मौजूदा नगरनिगम चुनाव में प्रयागराज के मेयर पद के लिए उसे बहुजन समाज पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने की तकरीबन तैयारी थी। लेकिन बदले हुए घटनाक्रम में स्थितियां बदल चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी अतीक मामले की सुनवाई में तेजी आने के बाद से ही शाइस्ता की उम्मीदवारी पर ब्रेक लगा चुकी थी। अलबत्ता वह भी पुलिस कस्टडी में हुई हत्या को मुद्दा बना रही है। विपक्षी राजनीति की यह पूरी कवायद कम से कम मौजूदा नगर निकाय चुनावों में मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर लुभाने की दिशा में उठाया गया कदम लग रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोटर अब भी समाजवादी पार्टी की ओर जाएंगे? क्या अतीत की तरह उनकी सबसे पसंदीदा पार्टी समाजवादी पार्टी बनी रहेगी? या फिर मुस्लिम आधार वोटर बहुजन समाज पार्टी की ओर खिसक जाएगा? अतीत में मुस्लिम वोटर बहुजन समाज पार्टी का भी साथ दे चुका है। इसलिए ऐसा आकलन बेमानी भी नहीं कहा जा सकता।

मुस्लिम वोटरों के भावी रूझान पर चर्चा से पहले जान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के वोटरों के आंकड़े क्या हैं। आंकड़ों को मुताबिक, राज्य में करीब 20 फीसद मुस्लिम मतदाता हैं। राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 143 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का ज्यादा असर है। इनमें से 70 सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 20 से 30 प्रतिशत के बीच है। जबकि 73 सीटें ऐसी हैं. जहां मुसलमान मतदाताओं की संख्या 30 प्रतिशत से ज्यादा है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की करीब तीन दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं, जहां मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनावों में बाजी मारते रहे हैं। इसी तरह करीब 107 विधानसभा सीटों पर करीब हर चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने ही चुनावी नतीजों को प्रभावित किया है। राज्य में तीस प्रतिशत से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले 14 जिले हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला जिला मुरादाबाद है, जहां 50.80 प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या है। राज्य में बारह जिले ऐसे हैं, जहां की आबादी में मुसलमानों की भागीदारी 15 से लेकर तीस प्रतिशत के बीच है। बागपत में जहां मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी 27.98 प्रतिशत है, वहीं अमेठी में 20.06 प्रतिशत है। अब सवाल यह है कि अतीक अहमद प्रकरण के बाद क्या मुसलमान अब भी समाजवादी पार्टी के प्रति उतना ही झुकाव रखेंगे? इसका जवाब स्थानीय मीडिया रिपोर्टों और यू ट्यूब चैनलों पर प्रसारित होने वाले मुस्लिम समुदाय के इंटरव्यू में एक हद तक दिख रहा है। मुस्लिम समाज मान रहा है कि अतीक का ऐसा हाल नहीं हुआ होता, अगर उमेश पाल हत्याकांड के बाद समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में मामले को सरगर्मी के साथ नहीं उठाया होता। मुसलमान आबादी का बड़ा हिस्सा इस बात को स्वीकार करने से हिचक नहीं रहा है कि अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को उकसाया और उसके बाद ही योगी ने विधानसभा में चर्चित बयान दिया कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उसी बयान का संदेश गया और अतीक अहमद का साम्राज्य ढह गया। पहले उसके बच्चे का एनकाउंटर हुआ और फिर दोनों भाई मार दिए गए। अतीक चाहे जितना भी बड़ा माफिया हो, उसे लेकर कम से मुस्लिम समुदाय में सहानुभूति दिख रही है और इसे जाहिर करने से वह हिचक भी नहीं रहा है। अतीक अहमद की हत्या के लिए वह समाजवादी पार्टी के उकसावे को सीधे-सीधे जिम्मेदार ठहरा रहा है। मुस्लिम बुद्धिजीवी इस मुद्दे पर खुलकर भले ही न बोल रहे हों, लेकिन निजी बातचीत में वे भी समाजवादी पार्टी से निराश दिख रहे हैं।

कर्नाटक भाजपा : बगावत की राह पर नेता

समीर चौगांवकर

सोमवार को कर्नाटक में हुबली धारवाड़ सीट पर भाजपा ने महेश टेंगीनकाई को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। वो भाजपा के प्रदेश महासचिव हैं और लिंगायत समुदाय से आते हैं। लेकिन सोमवार को जब तक भाजपा इस सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित करती जगदीश शेट्टार भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जा चुके थे। जगदीश शेट्टार इसी सीट से चुनाव लड़ते आये हैं और इस बार भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया था।

जगदीश शेट्टार अकेले नेता नहीं है जिन्होंने ऐन चुनाव से पहले भाजपा में बगावत की है। जगदीश शेट्टार के अलावा कर्नाटक भाजपा के एक महत्वपूर्ण नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने भी भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस का हाथ मजबूत करने का फैसला ले लिया है। सावदी ने 14 अप्रैल को कांग्रेस का दामन थाम लिया था। अब वे कांग्रेस टिकट पर अथानी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे।

कर्नाटक में लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर दक्षिण के इस दरवाजे को मजबूत करने में जुटी भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं की बगावत से परेशान है। कर्नाटक विधानसभा में मतदान के लिए 22 दिन से भी कम वक्त बचा है, लेकिन भाजपा अपने नेताओं के विद्रोह से उबर नहीं पा रही है।

किसान बाहुल्य और लिंगायतों के वर्चस्व वाले कित्तूर को पहले मुम्बई कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। कित्तूर कर्नाटक के छह जिले बेलगावी, हुब्बली धारवाड़, विजयपुर, हावेरी, गदग और बागलकोट में कुल 50 विधानसभा सीटें आती है। कर्नाटक की 224 सदस्यों वाली विधानसभा का यह लगभग 22 फीसदी है।

2018 के विधानसभा चुनाव में 50 सीटों में से 30 भाजपा को मिली थी। कांग्रेस को 17 और जेडीएस को केवल 2 सीटें हाथ लगी थी। 2013 के चुनाव में यहा कांग्रेस को 31 और भाजपा को 13 सीटें मिली थी। 2013 में भाजपा के दिग्गज नेता येदियुरप्पा ने अपनी अलग पार्टी कर्नाटक जनता पक्ष बनाकर चुनाव लड़ा था और इस क्षेत्र में भाजपा को तगड़ा नुकसान पहुंचाया था। इस साल 2023 के चुनाव में जगदीश शेट्टार के विद्रोह के बाद भाजपा को इस क्षेत्र में नुकसान होना तय है।

येदियुरप्पा खुद कह चुके हैं कि शेट्टार के कारण 20 सीटों के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। इस क्षेत्र में भाजपा लिंगायत मतों पर निर्भर रही है। भाजपा के सबसे बड़े लिंगायत नेता येदियुरप्पा इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे है और लिंगायत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई भले मुख्यमंत्री हो लेकिन भाजपा ने इस बार उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। लिंगायतों के एक और नेता जगदीश शेट्टार जो इसी कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने भाजपा से बगावत करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसे में भाजपा के लिए इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाना आसान नहीं होगा।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार का टिकट भाजपा हाईकमान ने क्यों काटा, इसका कारण कर्नाटक भाजपा के किसी भी नेता को नहीं मालूम। कर्नाटक के दिग्गज नेता येदियुरप्पा, प्रदेश संगठन महामंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने भी शेट्टार को टिकट देने की पैरवी की थी। लेकिन प्रदेश के दिग्गज नेताओं के कहने के बाद भी भाजपा हाईकमान ने जगदीश शेट्टार को टिकट न देने का फैसला किया।

करीब तीन दशक के लंबे राजनीतिक सफर के बाद भाजपा का साथ छोड़ने वाले पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार के परिवार का जनसंघ से पुराना रिश्ता रहा है। जगदीश शेट्टार के पिता शिवप्पा शेट्टार हुब्बल्ली-धारवाड़ निगम में जनसंघ के पहले महापौर थे जबकि चाचा सदाशिव शेट्टार ने 60 के दशक में उत्तर कर्नाटक में जनसंघ के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सदाशिव शेट्टार 1967 में राज्य विधानसभा के लिए चुने गए पहले चार जनसंघ नेताओं में से एक थे। तब पहली बार दक्षिण में जनसंघ ने जीत दर्ज की थी। जगदीश शेट्टार ने 1994 में हुबली ग्रामीण सीट से मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को हराकर विधानसभा में प्रवेश किया था। बाद में शेट्टार विपक्ष के नेता, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जैसे पदों तक पहुंचे।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और अब भाजपा से बगावत कर कांग्रेस में शामिल हो चुके जगदीश शेट्टार ने संपर्क करने पर बातचीत में साफ कहा कि भाजपा हाईकमान उनके टिकट काटने का कोई ठोस और उचित कारण नहीं बता सका। शेट्टार ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने उन्हें भविष्य मे कहीं समायोजित करने का आश्वासन जरूर दिया लेकिन टिकट काटने का कारण नहीं बता सके। शेट्टार का कहना है कि दूसरे दलों के नेताओं को तुंरत टिकट दिया जाता है लेकिन अपने ही समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। शेट्टार ने कहा कि वह अपमानित महसूस कर रहे हैं और बिना किसी वजह के उनका टिकट कटने के कारण कांग्रेस के टिकट पर अपनी परंपरागत सीट पर ताल ठोक रहे हैं।

कर्नाटक सरकार में मंत्री और 6 बार के विधायक एस अंगारा, राज्य के उपमुख्यमंत्री रह चुके विधायक लक्ष्मण सावदी, हुबली-धारवाड़ (सेंट्रल) सीट से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, मुदिगेरे से विधायक एमपी कुमारस्वामी, दो बार के हावेरी से विधायक नेहरू ओलेकर, होसदुर्गा से विधायक गोलीहट्टी शेखर, कुदलिगी से विधायक एनवाई गोपालकृष्ण के अलावा टिकट नहीं मिलने पर पूर्व विधायक सोगडू शिवण्णा और पूर्व सांसद एस. पी. मुद्दहनुमेगौड़ा ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की है। तुमकूरु नगर क्षेत्र के पूर्व विधायक शिवण्णा ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। शिवण्णा ने कहा है कि वे लगातार 4 बार जीते। 2013 में हारे और 2018 में आलाकमान के आदेश पर मुकाबले से पीछे हटे थे। कुणिगल क्षेत्र से टिकट मिलने की उम्मीद के साथ भाजपा में शामिल हुए पूर्व सांसद एस.पी. मुद्दहनुमेगौड़ा ने भी पार्टी छोड निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की है।

केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों के बाद प्रदेश के शीर्ष नेता डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, सीएम बसवराज बोम्मई, पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के अलावा प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील असंतुष्टों को समझाने और शांत करने के प्रयास कर रहे हैं। संघ के कुछ नेताओं को भी इस काम पर लगाया गया है। केंद्रीय नेता भी नाराज वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है, लेकिन फिलहाल इसका कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है।

हिमाचल प्रदेश में बगावत के कारण सत्ता गंवा चुकी भाजपा के लिए कर्नाटक में भी अपने नेताओं की बगावत के कारण सत्ता की राह मुश्किल हो गई है। 224 विधानसभा सीटों में से 35 सीटों पर भाजपा विपक्ष के साथ साथ अपने ही बागी नेताओं से तगड़ी चुनौती का सामना कर रही है। इसमें से कितनी सीटें भाजपा हारती है इसके लिए 13 मई का इंतजार करना होगा, जब चुनाव परिणाम घोषित किये जाएंगे। लेकिन इतना तो साफ दिख रहा है कि केन्द्रीय नेतृत्व का अत्यधिक दखल, स्थानीय नेताओं में तालमेल का अभाव, चुनाव जीतने के लिए गुजरात फार्मूले को लागू करने की जिद्द में बीजेपी यहां इतनी उलझ गयी है कि ऐन चुनाव के मौके पर उसे सुलझा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

शाण्डिल्यापोनषद् (भाग-09)

गतांक से आगे...

योगी सुखासन पर बैठकर दाहिनी नाड़ी के द्वारा बाहर की वायु को अन्दर की ओर खींचकर सिर के बालों से लेकर पैर के नख की नोंक तक में वायु को रोक कर अर्थात् कुम्भक करके बायीं नाड़ी के द्वारा वायु को बाहर निकाले अर्थात् रेचक करे। ऐसी क्रिया करने से कपाल की शुद्धि होती है और नाड़ियों में रहने वाले समस्त रोगों का पूर्णतया विनाश ही हो जाता है।

हृदय से लेकर कण्ठ पर्यन्त शब्द के साथ दोनों नासिका छिद्रों के द्वारा धीरे-धीरे वायु को खींचकर शक्ति के अनुसार कुम्भक करने के बाद इड़ा नाड़ी के द्वारा रेचक करना चाहिए। यह क्रिया चलते हुए तथा खड़े हुए भी करते ही रहना चाहिए, क्योंकि इस क्रिया से कफ का शमन और जठराग्नि की वृद्धि होती है। मुख के द्वारा सीत्कार अर्थात् सी-सी करते हुए वायु अन्दर भरकर शक्ति के अनुसार कुम्भक करने के पश्चात् दोनों नासिका छिद्रों द्वारा रेचक की क्रिया करनी चाहिए। इससे भूख-प्यास, आलस्य अथवा निद्रा का प्रादुर्भाव नहीं होता। जिह्वा द्वारा वायु को अन्दर खींचकर शक्ति के अनुसार कुम्भक करके दोनों नासिका छिद्रों द्वारा रेचक करना चाहिए। इससे गुल्म (गोला), तिल्ली, ज्वर, पित्त और भूख आदि रोगों का शमन हो जाता है। अब कुम्भक के सन्दर्भ में कहते हैं, उसके दो भेद हैं- (1) सहित और (2) केवल रेचक तथा पूरक से जो संयुक्त हो, उसे सहित और उनसे जो रहित हो, वह केवल है। इसमें से केवल जब तक सिद्ध न हो, तब तक सहित का अभ्यास करते रहना चाहिए और जब केवल कुम्भक सिद्ध हो जाता है, तब योगी को तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। केवल कुम्भक के द्वारा ही कुण्डलिनी जाग्रत् हो जाती है। इस सिद्धि के पश्चात् योगी-साधक कृश शरीर से युक्त, प्रसन्न मुख वाला, निर्मल नेत्रों से सम्पन्न, नाद श्रवण करने वाला, समस्त रोगों से रहित, बिन्दु को जय करने वाला (ब्रह्मचर्यसिद्ध) तथा प्रज्वलित जठराग्नि से युक्त हो जाता है। अन्त:करण में लक्ष्य निहित हो तथा बाह्य की दृष्टि निमेष-उन्मेष अर्थात् पलक झपकने से विहीन हो, यही वैष्णवी मुद्रा है तथा इसे ही समस्त तन्त्र शास्त्रों में गुप्त रहस्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। अन्तर्लक्ष्य में जिस योगी का चित्त और पवन विलय को प्राप्त हो गया हो, वह योगी साधक सततं निश्चल नेत्रों द्वारा बाहर की ओर नीचे की तरफ देखता हो, किन्तु इसके अतिरिक्त और कुछ न देखता हो, यही खेचरी मुद्रा है। यह केवल लक्ष्य में ही एकतान एवं मङ्गलमयी होने के कारण वैष्णवी मुद्रा भी कही जाती है। उसमें शून्य एवं अशून्य रहित परमतत्त्व अविनाशी पद रूप में प्रकाशित होता रहता है। अर्ध उन्मीलित नेत्रों से युक्त, एकाग्र मनवाला तथा नासिका के अग्रभाग पर स्थित दृष्टि से सम्पन्न योगी अचल भाव को पाने के पश्चात् सूर्य एवं चन्द्र नाड़ी को भी विलय करा देता है।

क्रमश:...

राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस आज

प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लोक सेवकों को समर्पित है जो कि देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं, साथ ही नीति निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सिविल सेवकों के योगदान को शब्दों में बयां करना इतना आसान नहीं है इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन को सिविल सेवकों को समर्पित किया जाता है। उनके सराहनीय कार्यों के लिए इस दिन उन्हें सम्मानित भी किया जाता है।

राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस का इतिहास

21 अप्रैल को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया था। दिल्ली के मेटकाफ हाउस में उन्होंने सिविल सेवकों को अतीत के अनुभव पीछे छोड़ राष्ट्रीय सेवा को अच्छे से करने की भावना पर भाषण दिया। इस दिन उन्होंने सिविल सर्वेंटों को देश की स्टील फ्रेम कहकर संबोधित किया था। 2006 में इसी दिन एक विशाल समारोह सिविल सर्वेंटों के लिए आयोजित किया गया था। इसके बाद से प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।

राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को उनके द्वारा वर्षभर में किए गए असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है। इस दिन अधिकारी मिलकर आने वाले सालों की योजना पर भी विचार करते हैं एवं उनपर विभिन्न मतों को प्रकट करते हैं। कई संस्थानों में सिविल सर्वेंटों को बतौर अतिथि आमंत्रित किया जाता है जहां पर वे अपने कार्य से जुड़े अनुभवों को बांटते हैं।

ब्रिटिशकाल में आया शब्द 'सिविल सर्वेंट'

सिविल सर्वेंट शब्द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान प्रचलन में आया था। यहां के नागरिक कर्मचारी प्रशासनिक नौकरियों में शामिल थे। ब्रिटिशर्स इन्हें सिविल सर्वेंट अर्थात लोक सेवक कहकर पुकारते थे। इन सेवाओं को शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा की गई। उसके पश्चात चार्ल्स कॉर्नवॉलिस ने इनमें सुधार किये इसलिए वे 'भारत में नागरिक सेवाओं के पिता' कहलाए।

यह सेवाएं हैं शामिल

भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस, भारतीय पुलिस सर्विस, आईपीएस, भारतीय विदेश सेवा, आईएफएस और अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवा समूह अ और ब के लिए भारत में कई सारे विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। यह सभी परीक्षाएं भारतीय लोक सेवा आयोग के तहत आती हैं। जिनमें चयन होने के बाद आगे विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है।

सिविल सेवा दिवस मनाने का उद्देश्य

सिविल सेवा अधिकारियों के कार्य और प्रयासों को प्रेरित करना और उनकी सराहना करना। केंद्र सरकार सबसे अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों और समूहों को पुरस्कार देती है। केंद्र सरकार इस अवसर का उपयोग सिविल सेवाओं के तहत विभिन्न विभागों के काम का मूल्यांकन करने के लिए करती है।

इस दिन ज्यादातर केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लोक प्रशासन के क्षेत्र में उनकी असाधारण सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाता है।

जंग में जीत के लिए कितना तैयार है भारत?

सरस चंद्र त्रिपाठी

भारत-चीन के बीच लगातार चल रहा तनाव हमारे देश में लोगों के मन में सेना, हथियार, चीन और भारत की शक्ति की तुलना, परमाणु बम जैसे विषयों पर बहुत उत्सुकता और कुतूहल पैदा कर रहा है। भारत में मिलिट्री सर्विस अनिवार्य नहीं है इसलिए रक्षा विषयों में आम जनता की जानकारी काफी कम है। उनमें से दो प्रश्न अधिक होते हैं-एक भारत के पास प्रर्याप्त हथियार/गोला-बारूद है? दूसरा अगर चीन ने एटम बम प्रयोग किया तो? इनका सटीक उत्तर विशेषज्ञों के पास भी नहीं है और इसका उत्तर देने का प्रयास करना भी उचित नहीं। परन्तु कुछ बातें समझना बहुत आवश्यक है। इनको समझ लेने से बहुत सी शंकाओं का स्वत- समाधान हो जाएगा। बहुत कम लोग हैं जो इन विषयों को ठीक से समझते हैं। सारे हथियारों को आम तौर पर दो भागों में बांटा जाता है- रणनीतिक और युद्धनीतिक।

रणनीतिक हथियार उनको कहा जाता है जो असल में युद्ध में प्रयोग करने के लिए होते ही नहीं हैं। ऐसे हथियार अत्यंत भयावह स्थिति में प्रयोग किये जाते हैं, जो परस्पर विनाश की ओर ले जाते हैं। ये हथियार अधिकतर युद्ध की रोकथाम के लिए होते हैं। ये डिटेरेंट होते हैं। इनकी खास बातें निम्न प्रकार हैं-1.रणनीतिक हथियार सामूहिक नरसंहार के अस्त्र- शस्त्र (वेपंस ऑफ मास डिस्ट्रक्शन) होते है। यानी ये हथियार महाविनाश के हथियार होते हैं जिसमें बिना भेदभाव के नरसंहार एवं महाविनाश होता है। 2. यह हथियार अधिकतर युद्ध में प्रयोग किए जाने के लिए नहीं बल्कि युद्ध को रोकने के लिए होते हैं। 3. यह हथियार सशस्त्र सेनाओं (आर्म्ड फोर्सेज) के पास ही होते हैं और चलाने का सारा प्रशिक्षण भी सिर्फ सेना (थल, जल, और

वायुसेना) के ही पास होता है मगर चलाने का अधिकार नहीं होता। 4. इन हथियारों को चलाने का निर्णय देश के शिखर नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (भारत में सुरक्षा पर निर्णय लेने के लिए बनी सर्वोच्च संस्था यानी कि मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति) लेती है। इसमें प्रधानमंत्री के अलावा वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री होते हैं। 5. स्ट्रैटेजिक वेपंस का प्रयोग आमतौर पर दो स्थितियों में ही होता है- एक, जब शत्रु ने उस हथियार का प्रयोग पहले करके हमारा बहुत बड़ा विनाश कर दिया हो या दो, हमारा बहुत बड़ा भूभाग, सभी संसाधनों सहित, शत्रु ने छीन लिया हो जिससे देश की एकता/अखंडता के ऊपर बहुत गंभीर खतरा पैदा हो गया हो।

इस परिभाषा के बाद अब यह समझना आसान होगा कि इस कैटेगरी में कौन से हथियार आते हैं। इसमें सिर्फ एक ही हथियार आता है जिसे हम परमाणु बम या एटम बम कहते हैं। इसके अलावा न्यूट्रॉन बम या हाइड्रोजन बम भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इन हथियारों को रखने के लिए और संचालित करने के लिए एक पूरी अलग से कमांड है जिसे ट्राई सर्विस स्ट्रेटजिक कमांड कहा जाता है। इसकी कमांड सेना के अति वरिष्ठ अधिकारी (जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होता है) के हाथ में होती है जिसे आर्मी कमांडर भी कहते हैं। यह सेनाध्यक्ष के ठीक नीचे और कोर कमांडर के ऊपर होता है। ट्राई सर्विस स्ट्रैटेजिक कमांड स्ट्रैटेजिक वेपंस के रखरखाव एवं संचालन में निपुण होते हैं परंतु इसे चलाने का अधिकार उन्हें नहीं होता। इसे चलाने का अधिकार सर्वोच्च नेतृत्व के ऊपर होता है और उनसे आदेश मिलने पर ही इन्हें चलाया जाता है।

रणनीतिक हथियारों के युद्ध टालने का प्रभाव हम रूस-अमेरिका सम्बन्धों से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। रूस और अमेरिका दोनों के पास एक दूसरे को पूरी तरह तहस-नहस करने की शक्ति है। इस कारण कोई युद्ध नहीं छेड़ना चाहता। क्योंकि दोनों को पता है कि यदि युद्ध हुआ तो दोनों तबाह हो जायेंगे। इसी को परस्पर विनाश कहते हैं। परस्पर तबाही के भय से दोनों में से कोई युद्ध आरम्भ नहीं करना चाहता। यही कारण है कि अमेरिका यूक्रेन के मामले में सीधे सम्मिलित नहीं हो रहा है। भारत के पास परमाणु बम ले जाने की क्षमता रखने वाली अग्नि मिसाइलें (मुख्यत: अग्नि-5), पृथ्वी मिसाइलें और ब्रह्मोस (यदि इसे परमाणु हथियार ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है) इस श्रेणी में आती हैं। ब्रह्मोस का प्रयोग जब लड़ाकू विमानों से नाभिकीय या हाइड्रोजन बम गिराने के लिए होता है तो ब्रह्मोस एक स्ट्रेटेजिक हथियार की श्रेणी में आ जाती है। असल में यह मिसाइल नहीं वरन उसमें ले जाने वाला वॉरहेड यह तय करता है की यह स्ट्रेटजिक हथियार है या टैक्टिकल।

दूसरी तरफ युद्धनीतिक हथियार वे सारे हथियार हैं जो स्ट्रैटेजिक की कैटेगरी में नहीं आते। ये ऐसे हथियार हैं जो पूरी तरह से युद्ध के दौरान सेनाधिकारियों के विवेक पर प्रयोग किए जाते हैं। इसमें आमतौर पर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और नाइट्रोजन बम जैसे वेपंस ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को छोड़कर बाकी सब हथियार आते हैं। इसमें राइफल पिस्टल जैसे छोटे हथियारों से प्रारंभ कर मोर्टार, तोप, टैंक, रॉकेट, मिसाइलें, लड़ाकू विमान, सभी प्रकार के युद्ध पोत सम्मिलित हैं। इन्हें परम्परागत हथियार भी कहते हैं।

संसार में बहुत कम देशों के पास रणनीतिक हथियार हैं। कुल मिलाकर 10 से अधिक नहीं है, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड, भारत, इजराइल, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और सम्भवत: ईरान। चूंकि रणनीतिक हथियार प्रयोग के लिए बने ही नहीं, इसीलिए प्रत्येक देश जिसके पास रणनीतिक हथियार हैं, परम्परागत हथियार और परम्परागत सेना में कोई कटौती नहीं करता। जिनके पास रणनीतिक हथियार हैं उन्हीं के पास विशालतम परम्परागत सेनाएं और सबसे शक्तिशाली परम्परागत और युद्धनीतिक हथियार भी हैं। मानव शक्ति की गणना के अनुसार सबसे बड़ी सेना चीन की, फिर अमेरिका, भारत, रूस, पाकिस्तान, फ्रांस के पास हैं।

भारत दोनों प्रकार के हथियारों से सज्जित है। इसीलिए भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है और चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। सैन्य शक्ति के मापदंड अनेकों हो सकते हैं परन्तु फायर पावर (द्वद्वह्नद्ग श्चश2द्गह्) को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। जिस प्रकार हमारी सेना में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण हो रहा है भारत दुनिया की तीसरी सबसे सशक्त सैन्य शक्ति बनने के द्वार पर खड़ा है। भारत की तैयारी दो फ्रंट पर लड़ने और दुश्मन को एंगेज करने की रही है। इसलिए अगर कभी ऐसी परिस्थिति बनती भी है तो हमारी ओर से तैयारी पूरी है।

गांधी आज

विवाह

विवाह से मनमाना भोग करने की छूट मिल जाती है यह विचार पापमय है। स्त्री-पुरुष का भोग एक ही उद्देश्य से धर्मयुक्त हो सकता है, वह है-दोनों की संतानेच्छा। इस इच्छा को पूरी करने का शुद्ध प्रकार विवाह है। विवाहेच्छु युवती या युवक अपने लिए वर या वधू खुद पसंद करें, यह साधारणत इष्ट नहीं है। इसमें मानसिक व्यभिचार के बारंबार और कभी-कभी शारीरिक व्यभिचार के भी अवसर उपस्थित होते हैं। इसके सिवा कम अनुभववाली युवावस्था तथा भोगेच्छा के आवेग में जो चुनाव होता है उसके बुद्धिमत्तापूर्वक होने की संभावना बहुत कम रहती है। इसलिए विवाहेच्छु को चाहिए कि वह अपनी इच्छा तथा विवाह के. विषय में उसने कोई शर्तें या निश्चय कर रखे हों (जैसे विधवा के साथ, जाति के बाहर पैसे के लेन-देन के बिना, विवाह करना, इत्यादि) तो उन्हें अपने बड़ों या बड़ों जैसे मित्रों को बता दे, और उनका ध्यान रखते हुए अपने लिए योग्य वर या वधू तलाश कर देने की उनसे प्रार्थना करे। बड़े लोग युवती या युवक के स्वभाव, गुण-दोष तथा विचारों को ध्यान में रखकर उनके अनुरूप जोड़ा ढूँढ देने का प्रयत्न करें। दोनों को एक-दूसरे के गुण-दोष से परिचित करा दें, दोनों के जीवन में कोई अवश्य जानने योग्य बात हुई तो उसे स्पष्ट कर दें। चुनाव में जो बात विशेष महत्त्व की हो सकती हो वह छिपाई न जाय। सब बातें बताने के बाद अगर युवक-युवती को परस्पर मिलकर परिचय अथवा बातचीत करने की ज़रूरत मालूम हो तो उन्हें मर्यादापूर्वक ऐसा करने का सुभीता बड़ों को कर देना चाहिए। इसके फलस्वरूप दोनों एक-दूसरे को स्वीकार करने का निश्चय करें तो उनका संबंध कर दिया जाय। दोनों में से एक भी अनिश्चित हो या रजामंद न हो तबतक संबंध न किया जाय। उस दशा में बड़ों को दूसरा स्था ढूँढना चाहिए। संबंध होने के बाद और विवाह के पहले स्पर्श की उचित मर्यादा में रहकर और ब्रह्मचर्य पालन का आग्रह रखते हुए दोनों एक-दूसरे के साथ पत्रव्यवहार रखें या मिले-जुलें तो इसमें दोष नहीं है। संयमी स्त्री-पुरुष इस अवधि में भी अपने भावी वर या वधू से भोग की बातें या कल्पनाएं न करके एक दूसरे का उत्कर्ष साधने वाली बातें और कल्पनाएं करेंगे।

संक्षिप्त समाचार

राजपूत छात्रावास भवन कोटा का विस्तारीकरण के लिए सीएम द्वारा 20 लाख की घोषणा

रायपुर। राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ उपसमिति रायपुर के अध्यक्ष पंकज कुमार भुवाल ने बताया कि विगत दिनों मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से राजपूत छात्रावास भवन कोटा रायपुर के विस्तारीकरण के लिए 50 लाख रुपए की मांग की गई थी। खुशी की बात है मुख्यमंत्री जी ने रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र भेंट मुलाकात के दौरान 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उपसमिति की ओर से मुख्यमंत्री जी का आभार। श्री भुवाल ने यह भी बताया कि ही महाराणा प्रताप जयंती पर सार्वजनिक अवकाश देने, निगम,मंडल,आयोग में समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने तथा सवर्ण समाज आयोग की स्थापना करने की माँग भी की गई थी। संवेदनशील मुख्यमंत्री ने इस पर भी विचार करने आश्वस्त किया है। डॉ. चंद्रशेखर सिंह ठाकुर पूर्व उपाध्यक्ष महासभा,श्रीमती वंदना राजपूत केंद्रीय महिला अध्यक्ष, सम्पत सिंह केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य, डॉ. शेर सिंह केंद्रीय निर्णायक सदस्य सहित समस्त केंद्रीय पदाधिकारियों, उपसमिति रायपुर के सभी सम्माननीय पदाधिकारियों, सदस्य गण को भी सहयोग प्रदान करने के लिए धन्यवाद एवं आभार। साथ ही अपेक्षा आगे भी समाज की यह एकजुटता बनी रहेगी।

नपा पार्षदों के बीच झूमाझटकी

बिलासपुर। तखतपुर नगर पालिका परिषद की सामान्य सभा में जमकर बवाल हो गया। बैठक में भाजपा पार्षद व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस आपस में भिड़ गए और हाथापाई शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्षद के बीच हुए विवाद का वीडियो भी सामने आया है। जो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि, इस विवाद के बाद मामला शांत हो गया और किसी ने कोई शिकायत नहीं की है।

आकृति देवांगन को पीएचडी की उपाधि

दुर्ग। बोरसी दुर्ग निवासी सुश्री आकृति देवांगन सुपुत्री अनिल कुमार देवांगन (सीएसईबी में पीए), श्रीमती सुशीला देवांगन को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई. उनके शोध का विषय था मुस्लिम और ट्रिपल तालक अधिनियम 2019 छत्तीसगढ़ में सामाजिक और विधायी ढांचे पर एक अध्ययन। उन्होंने गुरु घासीदास (केंद्रीय) विश्वविद्यालय से डॉ अर्चना यादव सहायक प्रोफेसर (सामाजिक कार्य विभाग) के मार्गदर्शन में अपनी पीएचडी पूरा किया। उन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ एसआरएफ की भी योग्यता प्राप्त की हैं और राष्ट्रीय और विदेशी भाषाओं के संस्थान से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर हैं। वे वर्तमान में कलिंगा विश्वविद्यालय में सामाजिक कार्य संकाय के रूप में कार्यरत हैं। तीन तलाक की मुस्लिम महिलाओं की स्थिति के प्रति उनका बहुत झुकाव है। उनके माता-पिता और सुपरवाइजर ने उन्हें ऐसे कठिन विषय में पीएचडी पूरी करने के लिए प्रेरित किया है। डॉ. दीपिका पांडे, श्री आशीष जॉनी केरकेट्टा, सुश्री अनुष्का अत्राम, खुशबू साहू और श्री आकाश उनके निरंतर प्रेरणास्रोत रहे।

छत्तीसगढ़ में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 619 मरीज मिले

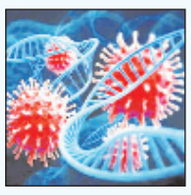

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार थमने का नहीं ले रहा है। कोरोना का वायरस तेजी से फैल रहा है। लगातार दिनों दिन कोरोना में बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कुल 6 हजार 606 सैंपलों की जांच की गई है। जिसमे पिछले 24 घंटे में 619 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं संक्रमण दर बढ़कर 9.37 पहुंच गया है। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा कोरोना केस मिले हैं। रायपुर में 83 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। रायपुर में आज कुल 83 नये मरीज मिले हैं, वहीं सरगुजा में 50, राजनांदगांव में 51, दुर्ग 39, रायगढ़ में 37, बिलासपुर में 35, बलौदाबाजार में 34, धमतरी में 31, कांकेर में 27, बेमेतरा 26, कवर्धा में 26, कोंडगांव 23, कोरिया 21, कोरबा में 21, सूरजपुर में 20, महासमुंद में 18 और बालोद में 16 मरीज मिले हैं। प्रदेश में आज आज एक मौत रायगढ़ में हुई है।

लवन शाखा नहर कार्य के लिए 12.26 करोड़ रूपए की स्वीकृति

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विकासखण्ड-पलारी/बलौदाबाजार की महानदी परियोजना के लवन शाखा नहर अंतर्गत वितरक शाखा के कोनारी माईनर, अमेरा माईनर, मगरचबा माईनर, घुलघुल माईनर, लवनबंद माईनर, छुईहा माईनर, धनगांव माईनर 01 एवं धनगांव माईनर 02 का रिमाडलिंग, सी.सी. लाईनिंग कार्य एवं स्ट्रक्चर्स का पुनर्निमाण/जीर्णोद्धार कार्य के लिए 12 करोड़ 26 लाख 35 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता महानदी परियोजना जल संसाधन विभाग को प्रदान की गई है। योजना के पूरा होने से 3065 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।

पशुओं के लिए चारा, पानी और छाया की व्यवस्था की जाए - बघेल

अधिकारी गौठानों का करें दौरा, गौठान समितियों की बैठकें आयोजित की जाए

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के 10 हजार से अधिक गौठानों में गर्मी को देखते हुए पशुओं के लिए चारा पानी और छाया की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को गौठानों का भ्रमण कर वहां पैरा के साथ ही हरे चारे, शेड और पानी की व्यवस्था कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों के आश्रित गांवों में भी मांग अनुसार गौठान की स्वीकृति दी जाए।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के तहत् से पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 4 करोड़ 40 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन अंतरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गौठान में होने वाली आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए अनिवार्य रूप से गौठान समितियों की बैठक करायी जाए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर कि राज्य के आधे से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए कहा कि नहरों से तलाबों में पानी भरने का काम त्वरित गति से करें, जिससे पानी की उपलब्धता रहेगी और जल स्तर बढ़ेगा। कार्यक्रम को कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने भी संबोधित किया।

गौरतलब है कि प्रदेश की 11 हजार पंचायतों में 10 हजार 6 सौ नब्बे गौठान स्वीकृत हुए हैं। जिसमें से 10 हजार से अधिक गौठान पूर्ण हो गये हैं। इन गौठानों में 5 हजार 3 सौ 98 गौठान स्वावलंबी हो गये हैं, जिनके द्वारा गोबर खरीदने के लिए 50 करोड़ 82 लाख रूपये की सहायता दी गई है। एक अप्रैल से 15 अप्रैल तक गौठानों में कुल 1.30 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हुई है। जिसके एवज में गोबर विक्रेताओं को अंतरित की जाने वाली 2.59 करोड़ रूपए की राशि में से 1.24 करोड़ की राशि कृषि विभाग द्वारा तथा 1.67 करोड़ रूपए का भुगतान स्वावलंबी गौठानों द्वारा किया गया है।

प्रदेश के 49 गौठानों में गोबर से पेंट तैयार करने की इकाई स्वीकृत की गई है जिसमें से 34 इकाईयां की स्थापना की जा चुकी है। 32 इकाई में पेंट का उत्पादन किया जा रहा है। इन इकाईयों से 87 हजार 8 सौ 27 लीटर पेंट की उत्पादन किया गया है तथा 47 हजार 5 सौ 47 लीटर पेंट के बिक्री से 97.08 लाख रूपये की आय अर्जित की गई है। राज्य के 33 जिलों के गौठानों में 20.20 लाख क्विंटल पैरा और 7 हजार 8 सौ 59 गौठानों में पानी की व्यवस्था की गई है।

गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को अब तक लगभग 439 करोड़ 73 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। राज्य में 15 अप्रैल 2023 तक गौठानों में 112.34 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। गोबर विक्रेताओं से आज की राशि अंतरण के पश्चात क्रय किए गए गोबर के एवज में 224 करोड़ 68 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को आज किये गये 1.81 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद 192.65 करोड़ रूपए की राशि दी जा चुकी है।

इस अवसर पर वर्चुअल रूप से वन मंत्री श्री अहमद अकबर, स्कूल शिक्षा श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम एवं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा एवम विनोद वर्मा, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री कमलप्रीत सिंह अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

आने वाली पीढ़ियों के लिए लोक संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन है उद्देश्य

रायगढ। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और तीज त्योहारों को सहेजने की दिशा में एक और पहल के रूप में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से किया। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की तर्ज पर राज्य के गैर-अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 'मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि योजना' का शुभारंभ किया गया है। यह योजना 61 विकासखंड सामुदायिक क्षेत्रों की 6 हजार 111 ग्राम पंचायतों में लागू होगी। इस योजना की इकाई ग्राम पंचायत होंगी। तीज-त्यौहार मनाने के लिए इस योजना में भी हर ग्राम पंचायत को दो किश्तों में 10-10 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। रायगढ़ जिले के दो विकासखंड रायगढ़ और पुसौर के 172 पंचायत योजना में शामिल हैं।

रिटायर्ड कर्मचारियों के रुके पेंशन को लेकर हाईकोर्ट के जज ने लिया संज्ञान

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में शासकीय नौकरी से रिटायर होने के बाद पेंशन मिलने में अक्सर कई अड़चनों का सामना करना पड़ता है। कर्मचारी रिटायर होने के बाद सालों तक पेंशन सुविधा से वंचित रहता है। पेंशन बनाने और पेंशन प्रक्रिया को पूरा करने वाले अधिकारी, कर्मचारी पेंशन शुरू करने के लिए अच्छी खासी घूस के रूप में रकम मांगते हैं। यही कारण है कि उनके पेंशन प्रकरण अक्सर कार्यालयों में रुके रहते हैं। इस मामले को लेकर अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के साथ शासकीय कार्यालयों में अटके पेंशन प्रकरण की पूरी जानकारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मंगवाई हैं।

रिटायर्ड गवर्नमेंट एंपलाई के पेंशन को लेकर अक्सर समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से खबरें छपती रहती हैं। पेंशन प्रकरण भुगतान में सालों तक लोगों को कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। अब इन रिटायर्ड कर्मचारियों से घूस की मांग भी होने लगी है। इस तरह के कई प्रकरण पिछले दिनों सामने आए थे, जिसको लेकर अब हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने पिछले दिनों हुए एक मामले को लेकर स्कूल शिक्षा सचिव और अन्य संबंधित अफसरों से प्रतिवेदन के साथ जानकारी मंगवाई हैं। जस्टिस गौतम भादुड़ी ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आनंद प्रकाश वारियाल के माध्यम से सभी प्रकरणों की जानकारी शपथ पत्र के साथ राज्य के कार्यालयों से मंगवाई हैं।

किस मामले के सामने आने पर लिया संज्ञान

पिछले दिनों एक समाचार आया था, जिसमें शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हुए प्राचार्य को 13 माह से अपने लंबित भुगतान के लिए भटकना पड़ रहा था। इस समाचार के आने के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया। महालेखाकार को भी इस संबंध में पत्र भेजने के निर्देश दिए।

खुद नहीं पता कब बनूंगा सीएम: सिंहदेव

सबको साथ लेकर कांग्रेस काम करेगी तो आएंगे अच्छे परिणाम

बिलासपुर। निर्माणाधीन जीएसटी भवन का निरीक्षण करने बिलासपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आगामी चुनाव में भाजपा- कांग्रेस की स्थिति पर कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए बहुत परंपरागत उपजाऊ भूमि रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन कभी भी ओवरकॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, पिछले चुनाव में भाजपा को सीटें मिली। ऐसे में भाजपा का मनोबल जरूर टूटा हुआ है। भाजपा हमेशा संघर्ष करते दिखी है लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं दिखती है। फिर भी अपने सामने की टीम को कम नहीं आंकना चाहिए। सबको साथ लेकर कांग्रेस काम करेगी तो अच्छे परिणाम की पूरी संभावना है।

कांग्रेस के आगामी चुनावी मेनिफेस्टो पर मंत्री सिंहदेव ने कहा कि पिछली बार की तरह मेनिफेस्टो बनाने का समय अब नहीं रहा, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम कर हमने सबका सहयोग सुझाव और मार्गदर्शन लिया था, उन

सुझावों को घोषणा पत्र में अंकित कर मेनिफेस्टो तैयार किया गया था, वैसा करने का समय अब नहीं बचा, उस तरह से घूमकर घोषणा पत्र में काम करने का समय अब नहीं है।

मंत्री टीएस सिंहदेव ने लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक मुद्दा बार-बार नहीं चलता। हिंदू धर्म की बात करना, दूसरे धर्म की बात करना, किसी को कम किसी को ज्यादा दिखाना, संघर्ष पैदा करना, कुछ लोगों को भावनात्मक रूप से यह प्रभावित कर सकता है लेकिन भारत की सभ्यता के वारिस देश के नागरिक परिपक्व हैं। आज नहीं तो कल इस बात को समझ लेंगे कि इसमें किसी का हित नहीं है। एक तरफ पूरे दुनिया को अपना परिवार मानने की बात होती है, दूसरे तरफ काट- काट के तोड़- तोड़ के ये चुनाव जीतने की बात करते हैं, यह मुद्दा लंबा नहीं चलेगा।

सीएम बनने के सवाल पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अभी तक जो परिस्थिति बनी हुई है मैं खुद नहीं जानता सीएम कब बनूंगा। राजनीति में आने का मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन विधायक बना, नेता प्रतिपक्ष बना, सीएम के लिए नाम चल पड़ा। सीएम बना नहीं बना लेकिन मीडिया के माध्यम से बिना बने सीएम बन गया। मैं यह कह दूं कि मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता ये असत्य होगा। लेकिन मैंने कभी भी मुख्यमंत्री बनने की पहल नहीं की, ये हाईकमान की बात रहती है, हाईकमान निर्णय करता है।

अवैध तरीके से संचालित दो आरा मशीनें की गई सील

■ इमारती लकड़ियों को काटकर चोरी-छिपे की जा रही थी सप्लाई

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (त्तक्रू) जिले में वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से संचालित दो आरा मशीनों को सील कर दिया है। इन आरा मशीनों से अवैध रूप से इमारती लकड़ियों की कटाई कर चोरी छिपे सप्लाई किया जा रहा था। दोनों ही आरा मशीनें बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थीं। मामला मरवाही वनमंडल परिक्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, वन विभाग को लगातार शिकायत मिल रही थी कि, इमारती लकड़ी के साथ ही सेमर की लकड़ियों की कटाई की जा रही है। वहीं यह भी पता चल रहा था कि क्षेत्र में बिना लाइसेंस के आरा मशीनों को संचालित किया जा रहा है। इन आरा मिलों में चोरी छिपे लकड़ियां पहुंच रही हैं और फिर उनकी सप्लाई की जा रही है। इस पर टीम ने आरा मिलों के कागजातों की जांच शुरू की। इस दौरान पेंड्रा के दुर्गा मंदिर के सामने स्थित आरा मिल और नया बस स्टैंड से बांधा तालाब जाने वाले सड़क पर स्थित दो आरा मिलें लाइसेंस नहीं दिखा सकीं। जांच के दौरान परिसर के अंदर एक-एक हाइड्रोलिक मशीन अवैध रूप से संचालित थीं। उन्हें सील कर दिया गया है।

बिलासपुर में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कोरोना पॉजिटिव

बिलासपुर। यूपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कोरोना पॉजीटिव हो गए। वे फिलहाल अवकाश के दौरान अपने गृहनगर बिलासपुर आये हुए थे। जहां वे कोरोना संक्रमित हो गए। उनका होम आइसोलेशन में इलाज किया जा रहा है। यूपी हाईकोर्ट के चीफ प्रिंतिकर दिवाकर पूर्व में छतीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस रहें हैं। वे बार कोटे से छतीसगढ़ हाईकोर्ट में ही जस्टिस बने हैं और यही से अपनी न्यायिक सेवा शुरू की। काफी सालों तक छतीसगढ़ हाईकोर्ट में पदस्थ रहने के बाद उनका यूपी की इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला हो गया। वे वहां बतौर जस्टिस के रूप में काम करते हुए हाल ही में हुए हाईकोर्ट जजों की पदोन्नति सूची में पदोन्नत होकर उत्तरप्रदेश के चीफ जस्टिस बन गए। उन्होंने अवकाश पर छतीसगढ़ आने से पहले दिल्ली के गुरुग्राम स्थित पैथोलॉजी लैब में अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया था। जिसमे उनकी रिपोर्ट कोविड़ पॉजिटिव आई है। यूपी के चीफ जस्टिस प्रिंतिकर दिवाकर फिलहाल अवकाश पर अपने घर बिलासपुर आये हुए हैं।

दुबई में बंधक बनाए गए दुर्ग जिले के गोपाल साहू की सकुशल घर वापसी

दुर्ग। दुबई में बंधक बनाए गए दुर्ग जिला के ग्राम डोमा निवासी गोपाल साहू समेत तीन लोगों की सकुशल घर वापसी हो गई है। उनका घर वापसी प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। दुबई में बंधक बनाए जाने की घटना को प्रदेश भाजयुमो सह कोषाध्यक्ष नितेश साहू ने जोर-शोर से उठाया था,जिससे प्रदेश भाजपा नेताओं का इस प्रकरण पर ध्यान गया और बंधक बनाए गए लोगों की सकुशल वापसी के लिए प्रयास तेज किए गए। जिसका सार्थक परिणाम सामने आया है। जिससे दुर्ग जिला के अलावा अन्य व्यक्तियों की सकुशल घर वापसी हो गई है। उनकी वापसी से परिजनों समेत ग्रामीणों में खुशियों का माहौल है। परिजनों द्वारा प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। दुबई में बंधक बनाए गए तीन लोगों की वापसी में अहम योगदान देने वाले प्रदेश भाजयुमो सह कोषाध्यक्ष नितेश साहू ने घटना के संबंध में सिलसिलेवार बताया कि काम की तलाश में दुर्ग जिला के ग्राम डोमा निवासी गोपाल साहू सहित तीन व्यक्ति साऊदी पहुंचे थे,लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि जिस काम के लिए उसे दलाल ने पैसे लेकर भेजा है। काम उससे बिलकुल अलग है और काम बहुत कठिन होने के साथ साथ खाने पीने की उचित व्यवस्था भी नहीं है, लगातार 15 घंटे काम कराकर अमानवीय व्यवहार किया जाता रहा। वापस जाने की बात कहने पर तीनों व्यक्तियों का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया था। घर से ऑनलाइन एक लाख रुपये मंगाने की डिमांड भी की गई पैसा मंगाने पर भी नहीं छोड़ा गया। बंधक बनाए गए व्यक्तियों ने आपबीती फोन के माध्यम से विडियो बनाकर अपने परिजनों को भेजा और मदद की गुहार लगाई। तब परिजन अपनी फरियाद लेकर प्रदेश युवा मोर्चा के सह कोषाध्यक्ष नितेश साहू एवं मीडिया प्रभारी आदित्य ताम्रकार के पास पहुंचे थे। जिस पर नितेश साहू ने अपनी गंभीरता का परिचय देते हुए मामले को जनदर्शन में उठाया। फिर भी प्रशासन की ओर से कोई उचित पहल नही की गई। जिससे परिजनों को निराशा हाथ लगी। नितेश ने बंधको व परिजनों की पीड़ा को छत्तीसगढ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया। राज्यसभा सांसद सु सरोज पांडेय ने इस विषय पर विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर विषय की गंभीरता और बंधकों की पीड़ा को सिलसिलेवार बताया। विदेश मंत्री ने तत्काल सऊदी के दूतावास में बात कर गोपाल साहू एवं उनके साथियों के देश वापसी के लिए वीज़ा जारी करने और दोषी कंपनी पर कार्यवाही करने की बात कही।

पर्यटन मंत्री ने आईएचएम में किया 50 सीटर हॉस्टल भवन का शिलान्यास

इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट के द्वितीय वार्षिकोत्सव के दौरान वार्षिक पत्रिका सुकुवा का विमोचन

■ 2021-22 में डिप्लोमा कोर्स के 63 छात्रों को विभिन्न प्रतिष्ठित होटल्स में मिली नौकरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन विभाग के अधीन संचालित नवा रायपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में कुल 138 छात्र अध्ययनरत है। इंस्टीट्यूट को और प्रभावी करने के लिए यहां बी.एस.सी. एचएचए (हास्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन) का कोर्स शुरू किया गया है जिसकी डिग्री दिल्ली के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू से प्राप्त होगी। खास बात ये है कि आईएचएम में किसी भी डिग्री व डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश हेतु आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है।

संस्थान के द्वितीय वार्षिक समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने इंस्टीट्यूट में छात्रों के रहने की सुविधा के लिए 50 सीटर हास्टल भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक श्री धनेन्द्र साहू, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष श्री अटल श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की उपाध्यक्ष श्रीमती चित्ररेखा साहू, पर्यटन विभाग के सचिव श्री

अम्बलगन पी.,एवं प्राचार्य श्रीमती रेखा शुक्ला उपस्थित थीं। वार्षिकोत्सव के दौरान ही मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू के द्वारा संस्थान के वार्षिक पत्रिका सुकवा का विमोचन भी किया गया।

पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने अपने संबोधन में इंस्टीट्यट आप होटल मैनेजमेंट रायपुर में अध्ययनरत् छात्र छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह संस्थान होटल हास्पिटैलिटी के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल करेगा। श्री साहू ने संस्थान में पढ़ रहे छात्रों के देश के बड़े होटल्स में प्लेसमेंट होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुसार संस्थान को बेहतर बनाने का काम जारी है और आने वाले समय में ये देश का सर्वश्रेष्ठ होटल मैनेजमेंट संस्थान बनेगा।

गौरतलब है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में तीन वर्षीय बीएससी डिग्री प्रोग्राम के 06 छात्रों का पहला बैच पास होने वाला है। इनमें से चार छात्रों का विभिन्न प्रतिष्ठित होटल्स में 4 चयन हो गया है । शैक्षणिक सत्र 2021-22 में डिप्लोमा कोर्स में अध्ययनरत 63 छात्रों को विभिन्न प्रतिष्ठित होटल्स में प्लेसमेंट हुआ है। इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट रायपुर को देश का अग्रणी संस्थान बनाने के उद्देश्य से पिछले 03 वर्ष में यहां अधोसंरचना का विस्तार करते हुए आधुनिक इंस्फास्ट्रक्चर स्थापित किये हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास परिषद के द्वारा हास्पिटैलिटी एवं टूरिज्म के अंतर्गत 18 कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जिसमें 08 कार्यक्रमों के प्रशिक्षण को संस्थान में प्रारंभ किए जाने की तैयारी चल रही है।

संस्थान के द्वितीय वार्षिकोत्सव के दौरान छात्र छात्रों के समूह ने होटल मैनेजमेंट अवेयरनेस पर नाटक, छत्तीसगढ़ी सुआ नृत्य, संस्कृतियों का संगम मेरा भारत जैसे विषयों पर मनमोहक प्रस्तुती दी । मुख्य अतिथि द्वारा द्वारा इस मौके पर छात्र छात्राओं को खेल, वाद विवाद, निबंध लेखन आदि क्षेत्र में पुरस्कृत भी किया।

संक्षिप्त खबरें

भीषण गर्मी के चलते स्कूल बंद करने की मांग

रायपुर। प्रदेश में इन दिनों गर्मी चरम पर है फिर भी छोटे-छोटे बच्चे तपती धूप में स्कूल जाने मजबूर है इसलिए कि स्कूल बंद नहीं हुआ है जबकि पिछले साल 20 अप्रैल को बंद करने का आदेश जारी हो गया था। सुबह 7 से 11 की पाली का भी कोई औचित्य नहीं हैं। गुरुवार को संस्था नवसृजन मंच द्वारा राज्यपाल एवं स्कूल शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया । राज्यपाल के सचिव और सहायक जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौपते हुए मांग कि की प्रदेश में इन दिनों तेज गर्मी से हर कोई झुलस रहा है, हालात यह है की दोपहर में लोग अपने घरों में बंद होना पसन्द कर रहे है लेकिन स्कूल खुले है और बच्चे मजबूरी में स्कूल जा रहे है ऐसे में स्कूल बंद करने की जगह दो पालियों में स्कूल खोलना सरासर गलत है उसकी जगह पिछले वर्ष जो आदेश स्कूल बंद रखने का 20 अप्रैल 2022 को जारी हुआ था वह यथावत रखा जाए। संस्था नवसृजन मंच के प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा ने बताया राज्यपाल जी के सचिव और सहायक जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मांग की गई की गई है स्कूल तत्काल बंद करने का आदेश जारी करें। साथ.साथ कोरोना का असर भी इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है अत- छोटे छोटे बच्चो के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए जनहित में स्कूलों को बंद रखना उचित होगा. ज्ञापन देने संस्था नवसृजन मंच के प्रतिनिधि मंडल में अमरजीत सिंह छाबड़ा डॉ देवाशीष मुखर्जी डॉ कांतिलाल जैन,सुनीता चंसोरिया,पदमा शर्मा,डा प्रीति सतपथी,मनोज जैन ,राहुल राव ,संदीप कसार शामिल थे ।

नोटिस के बाद भी नहीं हटाई बाउंड्रीवाल व बाथरूम, निगम ने तोड़ा निर्माण

दुर्ग। नगर निगम आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के निर्देश पर वार्ड 19 तितुरडीह, सब्जी मंडी प्रांगण पानी टंकी के पास तितुरडीह, अतिक्रमणकर्ता दिलबाल सिंह ढिल्लन आ.स्व.मंगल सिंह द्वारा कबाड़ कय विक्रय कार्य का व्यवसाय करते हुए स्थल पर पक्का निर्माण कार्य कर अतिक्रमण किया गया।एवं बाहर बाउंड्रीवाल व बाथरूम का भी पक्का निर्माण कर अवैध कब्जा कर लिया था। जिससे शासकीय,सार्वजनिक व अन्य भूमि बाधित हो रही थी।निगम के भवन शाखा द्वारा कब्जाधारियों को नोटिस के माध्यम से जानकारी दी जा चुकी थी। नोटिस के बाद भी बाउंड्रीवाल नही हटाया था इस क्रम में भवन शाखा अधिकारी प्रकाशचंद थावनी के मार्गदर्शन में कार्रवाही करके जेसीबी से निर्माण को तोड़कर हटाया गया।

नगरीय प्रशासन के काम-काज की समीक्षा

स्ट्रीट लाईट संधारण कार्य में घोर लापरवाही बरतने पर वेन्डर ईईएसएल को निरस्त करने के निर्देश

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आज गुरूवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर काम-काज की समीक्षा की। मंत्री डॉ. डहरिया ने समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश के नगरीय निकायों में वेन्डर ईईएसएल द्वारा स्ट्रीट लाईट मेन्टेनेंस में घोर लापरवाही तथा शिकायतों के आधार पर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल) को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर नगर निगम चिरमिरी के आयुक्त को शो-काज नोटिस जारी करने तथा बड़े बचेली के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निलंबित करने के भी निर्देश दिए।

मंत्री डॉ. डहरिया ने कहा कि ग्रीष्म ऋतु शुरू हो गया है। नगरवासियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है। लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने सभी आवश्यक

व्यवस्था सुदृढ़ कर लिया जाए, टैंकर का उपयोग कम हो आवश्यकता पड़ने पर ही टैंकर से जल प्रदाय किया जाए।

मंत्री डॉ. डहरिया ने राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजना श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों को सस्ते दर पर दवाईयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर जनहितकारी धन्वंतरी मेडिकल स्टोर शुरू किया गया हैं। हम सबका भी दायित्व है कि धन्वंतरी मेडिकल स्टोर का प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने मेडिकल मोबाइल यूनिट के कार्यों की भी जानकारी ली। उन्होंने ने निकाय द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की।

मंत्री डॉ. डहरिया ने बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न सभाओं, बैठकों एवं कार्यक्रमों में की गई घोषणाओं पर प्राथमिकता से अमल करते हुए शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री जी के घोषणा के विकास कार्यों का प्रस्ताव आगामी 10 मई तक अनिवार्य रूप से भेजने के निर्देश दिए।

मंत्री डॉ. डहरिया ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने अधूरे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निकायों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर हितग्राहियों को पीएम आवास निर्माण के लिए बैंक से समन्वय कर ऋण उपलब्ध कराए जाने की दिशा में भी विशेष पहल की जाए। मंत्री डॉ. डहरिया ने निकाय क्षेत्रों में मकानों, भवनों जो अनियमित है, उसका नियमितिकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं का छूट प्रदान करते हुए मकानों-भवनों का नियमितिकरण की जाए।

समय रहते बाल विवाह रोकें - तेजकुंवर नेताम

रायपुर। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेजकुंवर नेताम ने 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सभी जिलों को पत्र लिखकर समय रहते बाल विवाह की रोकथाम की कार्यवाही एक अभियान के रूप में योजनाबद्ध तरीके से करने कहा है। बाल विवाह किये जाने पर दोषियों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही भी की जाये । छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अनुशंसा पत्र जारी कर कहा है कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए समय रहते कार्यवाही करना जरूरी है। विवाह के दिन ही जाकर रोकथाम करने पर बहुत कठिनाईयों का समना करना पड़ता है। आयोग ने कलेक्टरों को बाल विवाह की रोकथाम के लिए पुलिस, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करने कहा गया है। आयोग ने कहा है कि पंचायत तथा क्लस्टरवार नोटल अधिकारियों की तैनाती की जाये । बाल विवाह रोकने के लिए पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का सहयोग भी लिया जाये । जिला प्रशासन द्वारा ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली जाये जहां पहले भी बाल विवाह के मामले अधिक आये हैं। गांव में सरपंचों द्वारा मुनादी और प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाये। सामुदायिक भवनों को विवाह के लिए देने से पहले तथा वैवाहिक कार्ड छापने के पहले वर व वधु की जन्मतिथि से संबंधित जानकारी लेकर आश्वस्त हो जायें।

आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं किया जाना दुखद है : रघु ठाकुर

रायपुर। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक रघु ठाकुर अपने अल्पप्रवास पर पहुंचे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि यह बहुत दुखद है कि पिछड़े वर्गो के आरक्षण संबंधी कानून पर अभी तक महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ ने हस्ताक्षर नही किए लोकतंत्र में कानून विधान का निर्माण करने का दायित्व संविधान में निर्वाचित विधायकों को दिया है। राज्यपाल एक नोडल एजेंसी है एक किसी कानून को वे तभी रोक सकते है जब कानून संविधान संगत न हो। यह किसी कानून के खिलाफ हो परंतु यह दोनों कारण नही है। अगर राज्यपाल की इससे वितर्क कोई राय है तो उन्हें प्रस्तावित कानून को मंत्रिमंण्डल के समक्ष पुन विचार के लिए भेजना चाहिए। परंतु ऐसा लगता है कि राज्यपाल महोदय राजनीतिक कारणों से कानून को रोकने का प्रयास कर रहे है। वैसे की भारत सरकार ने न तो वर्ष 2011 की जातिगत जनगणना की रपट प्रकाशित की है और न ही दूसरा कोई कार्यवाही की है। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी भारत सरकार से मांग करती है कि जातिगत जनगणना को सम्मलित किया जाये। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर मांग करेंगी कि छग के राज्यपाल की प्रस्तावित कानून पर स्वीकृति के लिए कहे और लोकतंत्र की रक्षा करें। लोसपा अपने स्थापना काल से ही संपूर्ण शराबबंदी के पक्षधर है पार्टी छग सरकार से अपील करती है कि प्रदेश में संपूर्ण शराबबंदी लागू करे इससे परिवार टूटने से बचेंगे विशेषता गरीबों के घर और महिलाएं सुरक्षित होंगे, शराब के नाम पर होने वाला भ्रष्टाचार समाप्त होगा, शराब माफिया का आंतक और रूपया समाप्त होगा। अगर छग सरकार यह पहल करेंगी तो यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। आज हालात यह है कि गांव गांव में शराब बिक रही है नौजवान पीड़ित यहां तक कि स्कूल के बच्चे भी शराबी बन रहे है।

लोकतंत्र का अर्थ तभी सार्थक हो सकता है चुनाव में काले धन की भूमिका समाप्त हो। एक सामान्य गरीब व्यक्ति भी चुनाव लडनें में सामान्य रूप से समर्थ हो परंतु एक्लोट्रान बॉड का कानून काले धन को सुक्रीत और संरक्षण देने वाला कानून है। इससे माध्यम से एक तरफ चुनाव में काला धन खेल रहा है।

गर्मी और लू से बचने दोपहर में काम नहीं, निर्देश जारी

रायपुर। बीते एक सप्ताह से छत्तीसगढ़ में तापमान में हुई वृद्धि और गर्म हवाओं के थपेड़ों को देखते हुए लोगों को गर्मी और लू से बचने की अपील की है। उन्होंने गर्मी और लू से बचाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों को ग्रीष्म ऋतु तथा लू से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने के संबंध में पत्र जारी किया गया है। पत्र में श्रम एवं रोजगार विभाग को गर्मी के समय (दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक) बाहरी काम एवं लू से बचने के लिए कार्यकालीन समय में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने कहा गया है। लू- तापघात से बचाव की तैयारी हेतु जिला स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने की बात कही गई है। इसके साथ ही सभी प्रमुख विभागों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

पत्र में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति करने के साथ ही एन.जी.ओ. लायंस क्लब, रोटरी क्लबों द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था,

में आवश्यक सहयोग लेने और शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रयास करने कहा गया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को सभी अस्पतालों में लू से बचाने के साथ ही लू से पिड़ित लोगों के उपचार के निर्देश दिये गये है। पशु चिकित्सा विभाग को पशुओं को लू से बचाने के लिए आवश्यक दवाईयों के साथ ही चारे पानी का इंतजाम रखने के निर्देश दिये है। परिवहन विभाग को जिलों के मुख्य बस स्टैण्ड/टर्मिनल पर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने कहा गया है।

शालाओं में पेयजल/ओ.आर.एस हो

शिक्षा विभाग को गर्मी के समय में शिक्षण संस्थानों के समय में आवश्यक परिवर्तन और शालाओं में शीतल पेयजल/ओ.आर.एस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है। इसके साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को मनरेगा में काम करने के लिए कार्य स्थलों पर पीने का पानी एवं छाया की व्यवस्था करने को कहा। वन विभाग को जंगल की आग से बचने के लिए वन क्षेत्र में निरंतर निगरानी रखने और वन क्षेत्रों के जंगली जानवरों एवं पक्षियों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने को कहा गया है।

जल संकट में त्वरित कार्यवाही

जल संसाधन विभाग को गर्मी को देखते हुए ट्यूबवेलों की मरम्मत तथा राज्य में किसी भी स्थान पर जल संकट होने की स्थिति में त्वरित कार्यवाही के लिये उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जल संकट वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से अक्रियाशील हेण्डपंपों की मरम्मत करवाने, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जल की कमी का आंकलन तथा पेयजल संकट से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिये गये हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

लुटिया डुबोने वाले ही स्टार प्रचारक, क्योंकि कांग्रेस में नेताओं का अकाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि मरकाम अपनी डूबती नैया और देश भर में कांग्रेस के अस्तित्व पर आए संकट की चिंता करने की बजाय भाजपा के बारे में फिजूल की टीका टिप्पणी करने में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कांग्रेस में नेताओं का अकाल है। इसलिए देश भर में पिटे पिटाये मोहरे स्टार प्रचारक के तौर पर पेश करना उसकी मजबूरी है। राहुल गांधी पूरे देश में कांग्रेस को हरवाते रहते हैं। उसके बाद भी स्टार प्रचारक हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जप्त करवाती है तो भी स्टार प्रचारक होती है। भूपेश बघेल जहां भी जाते हैं वहां कांग्रेस की लुटिया डुबा आते हैं। जबकि भाजपा के पास देश के सर्वाधिक मुख्यमंत्री हैं। ढेर सारे केंद्रीय मंत्री हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। संगठन के अन्य प्रभावशाली नेता हैं। भाजपा के पास नेताओं की कमी नहीं है। हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं। कांग्रेस बैसाखियों के सहारे है। भाजपा में समय-समय पर सभी को जिम्मेदारी मिलती है। जबकि कांग्रेस में सब चले हुए कारतूस हैं जो अब किसी काम के नहीं हैं। ऐसे में मरकाम भाजपा के ऊपर बयान देने की बजाय अपने गिरेबान में झांक लें।

पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से फिर गई एक जान, विफल साबित हुए मंत्री इस्तीफा दे- रंजना साहू

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा प्रवक्ता विधायक रंजना साहू ने पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से

बिलासपुर में मंगला लोखंडी के बीच सड़क के गड्ढे में गिरकर एक दूध कारोबारी की मौत पर मुख्यमंत्री से पर्याप्त मुआवजे की मांग करते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी ने सड़क पर गड्ढा खुला छोड़ दिया था। जिससे यह हादसा हुआ। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता विधायक रंजना साहू ने कहा कि ताम्रध्वज साहू से न तो गृह विभाग संभल रहा है और न ही लोक निर्माण विभाग। पूरे छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि बस्तर में स्थिति में सुधार हुआ है जबकि उनके ही विधायक के काफिले पर बीजापुर में हमला हो गया। गृहमंत्री के रूप में ताम्रध्वज साहू के सारे दावे खोखले साबित हुए हैं। लोक निर्माण मंत्री के रूप में उनके विभागीय कार्य का प्रदर्शन यह है कि उनके स्वयं के सरकारी आवास की दीवार साल में दो बार गिर जाती है। पूरे छत्तीसगढ़ की सड़कों की हालत जर्जर है। सड़क गड्ढों में बदल चुकी है। स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दौरान एक युवा खिलाड़ी को खराब सड़क के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वह समय पर रायगढ़ अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका।

जनता के हक के पैसों की हो रही है लूट- अमित चिमनानी

रायपुर। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जनता के हक के पैसों की लूट हो रही है। केवल पिछले वर्ष राज्य की कांग्रेस सरकार ने वैट और स्टेट जी एस टी से लगभग 18 हजार करोड़ की कमाई की है यह पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत ज्यादा है। पेट्रोल डीजल से भी राज्य ने रिकॉड कमाई की है लेकिन राज्य ने अपने कर से जनता को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई राहत नही दी। केवल एक साल में ही राज्य ने पेट्रोल डीजल से 6,520 करोड़ कमा लिए ।केवल साढ़े चार वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य को लगभग 2 लाख करोड रुपए दिए हैं तो आखिर यह पैसा गया कहां? अमित चिमनानी ने कहा राज्य की खुद की कमाई 20 प्रतिशत बढ़ी ,केंद्र की मोदी सरकार ने पांच गुना पैसा दिया लेकिन पैसा जनता तक नही पहुंचा, न राज्य ने अपने कर से पेट्रोल डीजल पर कोई राहत दी,न गरीबों का मकान बना, न गरीबों के घर में नल लगा, न गरीबों को केंद्र का भेजा चावल मिला, न संपत्ति कर माफ हुआ, न बेरोजगारी भत्ता मिला ,न नियमितीकरण हुआ न कांग्रेस के किए वादे अनुसार जनता को 20 लाख का मुफ्त इलाज मिला ,न 200 फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगी,न सड़के बनी,न पुल बने ,न स्टेडियम ,न ऑडिटोरियम बने,आखिरी पैसा गया कहां किसने इन पैसों की लूट की प्रदेश की जनता ये सवाल पूछ रही है।

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण राजनीतिक मुद्दा नहीं- रमन सिंह

धमतरी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह धमतरी में भाजपा की बूथ स्तरीय बैठक में शामिल हुए. रमन सिंह ने राहुल गांधी की याचिका खारिज

होने और धर्मांतरण सहित कई मुद्दों पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया.राहुल की याचिका खारिज होनी ही थी= रमन सिंह ने राहुल गांधी की याचिका को लेकर कहा कि सूरत कोर्ट में राहुल की याचिका तो खारिज होनी ही थी. वह याचिका स्वीकार हो ही नहीं सकती थी.रमन सिंह ने मंतूराम पवार के बयान पर प्रतिक्रिया दी है.उन्होंने कहा कि 2014 में अगर धमकी मिली थी, तो वह 10 साल बाद क्यों बता रहे हैं. उन्हें पहले बताना था. मंतूराम तो मंतूराम हैं, उनकी बात छोड़िए. कवासी लखमा का विधानसभा चुनाव में कटेगा टिकट ! धर्मांतरण के सवाल पर रमन सिंह ने कहा कि, धर्मांतरण कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है. लेकिन बस्तर से लेकर सरगुजा तक ईसाई मिशनरी सक्रिय है. धर्मांतरण के कारण छत्तीसगढ़ की सामाजिक समरसता कहीं न कहीं खराब हो रही है. रमन सिंह ने कहा कि भाजपा किसी तरह का सर्वे नहीं करवाती है. भाजपा में एक मान्य प्रक्रिया है, उसी के तहत टिकट बांटी जाती है. रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि पूरे प्रदेश में विकास ठप हो चुका है. धमतरी में महापौर बजट पेश करने से पहले ही भाग रहे हैं।

22 से 30 अप्रैल के बीच जिलों में होगा कांग्रेस की आवाज

रायपुर। वक्ता चयन कमेटी के सदस्यों की बैठक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में संपन्न हुई। बैठक में निर्णय हुआ कि कमेटी के सदस्य अपने प्रभार जिलों में 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किसी एक दिन तय करके जिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल एवं विभाग, प्रकोष्ठ तथा कांग्रेस विचारधारा से जुड़े लोगो को आमंत्रित कर उनसे साक्षात्कार कर हर जिले में न्यूनतम 10 वक्ता तथा अधिकतम की कोई सीमा नही की सूची प्रदेश मुख्यालय को सौपेंगे। वक्ता चयन में वक्ताओं से छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की योजना, मोदी सरकार की वायदा खिलाफी, छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर बनाम केन्द्र की बेरोजगारी दर, मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, केन्द्रीय एजेंसियो का दुरूपयोग, महंगाई, भारत के नवनिर्माण में कांग्रेस का योगदान, आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का योगदान, मोदी राज में देश की संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करने की साजिश, देश में किसानों की स्थिति बनाम छत्तीसगढ़ में किसानों की स्थिति विषयों पर उनकी राय ली जायेगी। बैठक में समन्वयक सुशील आनंद शुक्ला, सदस्यगण धनंजय सिंह ठाकुर, घनश्याम राजू तिवारी, विकास तिवारी, अभयनारायण राय, सुबोध हरितवाल, अजय साहू, संदीप साहू, सुरेन्द्र वर्मा, शारिक रईस खान, शशि भगत, विभोर सिंह, नितिन भंसाली, गीतेश गांधी, अमित श्रीवास्तव, विजय बघेल, वंदना राजपूत, अजय गंगवानी, ऋषभ चंद्राकर, रवि ग्वालानी, अनिल चौहान, रूपेश दुबे, योगेश पाणीग्रही, संजय देवांगन उपस्थित थे।

महिला चेंबर ने आयोजित किया निःशुल्क रक्त जांच शिविर

रायपुर। महिला चेंबर प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती मधु अरोरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफकॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज महिला चेम्बर द्वारा डॉ. पवन जोशी (हेल्थ एंड न्यूट्रिशियन स्पेशलिस्ट) एवं डॉ. प्रिया जोशी होम्योपैथी गोल्ड मेडलिस्ट के सानिध्य में 4 जनवरी 2023 को नए साल की नयी उमंग नई तरंग थीम के तहत रक्त जांच शिविर का आयोजन किया गया था जिसके नियमानुसार तीन माह बाद फालोअप हेतु आज दिनांक 20-04-2023 को पुन: रक्त जांच शिविर का आयोजन अनुपम नगर ट्विन टावर- जोशी होम्योपैथिक क्लिनिक एंड जोशी जिम में आयोजन किया गया। जिसमे अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं के साथ-साथ बच्चों एवं बुजुर्गों का नि:शुल्क रक्त जाँच एवं थायराइड जांच कराकर लाभ उठाया। श्रीमती अरोरा ने आगे कहा कि शिविर में मात्र 500/- में लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल, कंप्लीट ब्लड काउंट, लिपिड प्रोफाइल, आयरन प्रोफाइल, एचबीए1सी, कैलशियम, फास्फोरस का टेस्ट हुआ जिसका बाजार मूल्य 2200 रू. या उससे ज्यादा होता है। आज के इस मंहगाई के दौर में हमारे मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएं, बच्चे एवं बुजुर्ग इस प्रकार के मेडिकल चेकअप कराने से बचते है ताकि उन पर या परिवार पर कोई आर्थिक बोझ ना बढ़े यह जानते हुए कि इस तरह के कदम उनके स्वास्थ्य एवं परिवार के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। श्रीमती अरोरा ने आगे कहा कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार के स्वास्थ्य सुधार हेतु इस तरह के शिविर का आयोजन कर उन्हें लाभ पहुंचाने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

कांग्रेस ने किया दुर्ग संभाग की बूथ कमेटी की समीक्षा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सह सचिव विजय जांगिड़ ने दुर्ग संभाग के विधायकों, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक लिया। बैठक में सभी ब्लॉकों में बूथ कमेटियों के गठन की समीक्षा किया गया। जिन ब्लॉक अध्यक्षों ने अपने क्षेत्र के बूथ कमेटियों की सूची को जमा किया। उनका वहीं पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने फोन करके भौतिक सत्यापन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम द्वारा एक-एक बूथ एक-एक ब्लॉक अध्यक्ष जिलाध्यक्ष और एक-एक विधायकों से और प्रभारी महासचिव से संवाद कर बूथ गठन और उसकी भौतिकता पर जानकारी ली। 15 से 20 बूथ प्रभारियों को फोन लगाकर बूथ अध्यक्षों को फोन लगाकर क्रॉस चेक किया और जिसमें 90 परसेंट रिजल्ट आया। अभी तक जिन ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों ने अपने क्षेत्र की बूथ कमेटियों

का गठन नहीं किया है उनसे कहा गया है कि 28 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से बूथ कमेटियों का गठन कर प्रदेश कांग्रेस को जमा करें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि बूथ कमेटियों के गठन को सभी जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों, ब्लॉक अध्यक्षों को गंभीरता से लेना है 90 प्रतिशत से अधिक गठन हो गया शेष को शीघ्र 28 अप्रैल तक पूरा करना है। हमें हर हाल में मई माह से बूथ कमेटियों के प्रशिक्षण के काम को पूरा करना है। बूथ कमेटियों की मजबूती ही हमारी सरकार की 2023 में फिर से वापसी को सुनिश्चित करेगा। इस काम में कोताही बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। प्रभारी सह सचिव विजय जांगिड़ ने सभी पदाधिकारियों से जिम्मेदारीपूर्वक दिये गये टास्क को पूरा करने का निर्देश दिया। हर बूथ कमेटी का भौतिक परीक्षण किया जा रहा है। बूथ कमेटी की मजबूती से ही पार्टी मजबूत होगी। कार्यक्रम का समन्यवय महामंत्री एवं बूथ कमेटी के प्रभारी अरुण सिसोदिया ने किया।बैठक में बेहतर काम करने के लिये ब्लॉक अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी और प्रभारी महासचिव शाहिद भाई का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सम्मान कर प्रोत्साहित किया।बैठक में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, विधायक अरुण वोरा, विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे, विधायक छन्नी साहू, ममता चंद्राकर, इंद्रशाह मंडावी, बूथ कमेटी के प्रभारी महासचिव अरुण सिसोदिया, महामंत्री गण थानेश्वर पाटिला, शाहिद खान, आर.एन. वर्मा, जितेन्द्र कुमार साहू, लालजी चंद्रवंशी, दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष निर्मल कोसरे, दुर्ग शहर अध्यक्ष गया पटेल, मुकेश चंद्राकर, पदम सिंह कोठारी, संजीव गोमास्ता, नीलकंठ चंद्रवंशी, जिला महामंत्री राजीव गुप्ता, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार कश्यप, प्रमोद कुमार प्रभाकर, मुकुंद कुमार, नंद कुमार सेन, रामा विश्वकर्मा, नवीन जायसवाल, चेतन दास साहू, अब्दुल खान, अशोक बाम्बेश्वर, गोपाल राम प्रजापति, कोदूराम, सुमन गोस्वामी, रामेश्वर देवांगन, लुकेश वर्मा, महिप सिह भुवाल, अजय मिश्रा, राजकुमार पाली, राजकुमार साहू, अनिल मानिकपुरी, कोमलदास साहू, रितेश जैन, रतन यादव, सुरेश कुमार सिन्हा, हीरा सोनी, रमेश साहू, सूर्यकांत जैन, आसिफ अली, नोहरू कुमेटी, रामकुमार पटेल, गोल्डी आकाशदीप, भीखमचंद छाबेड़, दुर्गा गजबे आदि उपस्थित थे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.